राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

समय दर्शन

रायपुर एवं दुर्ग से प्रकाशित

ESTD : Since 2011

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर

निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

वर्ष 15, अंक 106 पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रूपये दुर्ग, शनिवार 28 फरवरी 2026 www.samaydarshan.in

संक्षिप्त समाचार

वांटेड अपराधी अनिल कुमार रेड्डी का यूएई से प्रत्यर्पण

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की मदद से वांटेड अपराधी के अनिल कुमार रेड्डी को यूएई से गिरफ्तार करके भारत लाया गया है। वह कई मामलों में धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग और आपराधिक धमकी के आरोपों में वांछित था। सीबीआई ने इसकी जानकारी दी। सीबीआई ने इंटरपोल चैनलों के जरिए यूएई से वांछित भगोड़े अनिल कुमार रेड्डी येदुला की भारत वापसी का समन्वय किया। भगोड़े अनिल के खिलाफ सीबीआई की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट (आईपीयूसी) ने विदेश मंत्रालय (एमईए) और एनसीबी-अबू धाबी के सहयोग से रेड नोटिस जारी कराया था। सीबीआई ने आंध्र प्रदेश पुलिस के अनुरोध पर 5 सितंबर 2022 को इस मामले में इंटरपोल के माध्यम से यह रेड नोटिस जारी कराया था। इसके बाद यूएई के अधिकारियों ने भगोड़े अनिल को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे भारतीय एजेंसी को सौंपने का फैसला लिया गया। गुरुवार को अनिल कुमार रेड्डी को दुबई पुलिस की एक टीम एस्कॉर्ट करके दुबई से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ले आई। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद एयरपोर्ट पर उसे आंध्र प्रदेश की पुलिस टीम को सौंप दिया गया।

अनजाने में गलती हुई, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक फिर से लिखी जाएगी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा आठ की पाठ्यपुस्तक में 'न्यायिक भ्रष्टाचार' से संबंधित अध्याय को लेकर कड़ी आपत्ति के बाद बुधवार को माफी मांग ली। परिषद ने स्पष्ट किया है कि विवादित अध्याय को उपयुक्त अधिकारियों से परामर्श के बाद दोबारा लिखा जाएगा। कोर्ट की फटकार के कुछ ही घंटों के भीतर एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट से पुस्तक हटा ली और उसके वितरण पर भी रोक लगा दी। संशोधित पुस्तक शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। एनसीईआरटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान जारी कर कहा, कक्षा आठ की पुस्तक के संबंधित अध्याय में कुछ अनुचित सामग्री और निर्णय संबंधी त्रुटि अनजाने में शामिल हो गई। एनसीईआरटी न्यायपालिका को सर्वोच्च सम्मान देता है और उसे भारतीय संविधान का संरक्षक तथा मौलिक अधिकारों का रक्षक मानता है। उन्होंने कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने या उसके अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न खड़ा करने का कोई इरादा नहीं था।

विपक्ष का वाक आउट

बालोद विधायक ने कहा क्षेत्र में करोड़ों के काम अटके

रायपुर। संवाददाता

विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया कि बजट में स्वीकृत हो चुके मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग से जुड़े करोड़ों के काम लंबे समय से अटके हुए हैं। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इससे इंकार किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की कि यदि काम अटके भी हुए हैं तो इसी सदन में स्वीकृति की घोषणा कर दें। वित्त मंत्री ने नियम प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा कर पाना संभव नहीं। इसके विरोध में सारे कांग्रेस विधायकगण नारेबाजी करते हुए सदन से वाक आउट कर गए। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा का सवाल था कि संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के बजट में सम्मिलित किन कार्यों के लिए 3 फरवरी 2026 की स्थिति में कितनी राशि की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है? कितनी राशि के कौन से कार्य वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के पास किन कारणों से तथा कब से लंबित हैं एवं इन कार्यों को कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ?वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी की ओर से जवाब आया कि विभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार संजारी-

बालोद विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत नवीन कार्यों के लिए 1 मई 2012 की स्थिति में 3 करोड़ तक के प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार प्राप्त थे, जिसे 14 मई 2025 में बढ़ाकर रू. 5 करोड़ किया गया, ताकि कार्यों की स्वीकृति में गति आए। प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश संबंधित विभाग व्दारा जारी किए जाते हैं। 3 फरवरी 2026 की स्थिति में वित्त विभाग में संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के कोई भी प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति पर सहमति हेतु लंबित नहीं है। श्रीमती सिन्हा ने कहा कि मेरे क्षेत्र में चाहे पीडब्लूडी हो या एरिकेशन, सभी तरफ के काम लंबित हैं। सभी कार्य वित्त में जाकर अटके हुए हैं। चौधरी ने कहा कि बजट में प्रावधानित कोई भी कार्य वित्त विभाग में सहमति के लिए आता है। आपके क्षेत्र में कई कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। बहुत सारे वित्तीय मसलों का रिफॉर्म हुआ है। बजट में नवीन मद की परिभाषा में संशोधन किया गया। पहला संशोधन 2011 में हुआ था, 2024 में फिर किया गया। प्रशासकीय स्वीकृति 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। ज्यादा से ज्यादा प्रशासकीय स्वीकृति हो सके इसलिए वित्तीय रीफॉर्म किया गया। बजट में बरसों से जो प्रावधान चले आ रहा था उसकी जगह वित्तीय प्रावधान बढ़ाया गया।पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आपने पूरी प्रक्रिया बता दी। बालोद का बताएं। बालोद तो जीरो है। चौधरी ने कहा कि वित्तीय स्वीकृति से संबंधित एक भी फाइल लंबित नहीं है।

विपक्ष ने गुमराह करने का आरोप लगाते हुए किया वाक आउट

फ्लाई ऐश एवं कोल डस्ट अवैध डंपिंग पर विधानसभा में चला आरोप-प्रत्यारोप

रायपुर। संवाददाता

विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने फ्लाई ऐश एवं कोल डस्ट की अवैध डंपिंग के मामले को उठाया। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी व्दारा यह कहे जाने पर कि ऐसे मामलों में पिछली सरकार की तुलना में हमारी सरकार ज्यादा कार्यवाही कर रही है, कांग्रेसी विधायगण भड़क गए और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए वाक आउट कर गए। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक उमेश पटेल का सवाल था कि रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित उद्योगों में कितने कितने उद्योगों से फ्लाई ऐश डंप किया जाता है? वर्ष 2023-24, 2024-25 से लेकर विगत 4 फरवरी तक की स्थिति में अवैध पलाई ऐश डम्प किए जाने के कितने मामले सामने आए और क्या कार्यवाही की गई? क्या बिना अनुमति के फ्लाइ ऐश डम्प करने का मामला प्राप्त हुआ है? रायगढ़ जिला के फ्लाई ऐश एवं कोयला परिवहन के कारण दूषित पर्यावरण के सुधार हेतु क्या कार्य योजना है? आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी की तरफ से जवाब आया कि उक्त अवधि में रायगढ़ जिला अंतर्गत 24 ताप

विद्युत संयंत्रों व्दारा राख का उपयोग भू-भराव/खदान भराव में किया जा रहा है। उक्त ताप विद्युत संयंत्रों में से 6 ताप विद्युत संयंत्रों व्दारा स्वयं के निर्मित ऐश डाईक में भी अस्थाई रूप से राख का भण्डारण किया जाता है। उक्त अवधि में राख के अवैध या बिना अनुमति डंपिंग के 49 मामले मंडल के संज्ञान में आये हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यालय आदेश 26 जून 2024 के माध्यम से उद्योगों से कच्चे माल,उत्पाद,अपशिष्ट के सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान प्रदूषण के रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया गया है, जो कि 1 अगस्त 2024 से प्रभावशील है। उद्योगों से जनित ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु परिवहन की निगरानी बाबत औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (आईडब्ल्यूएमएमएस) संचालित की गई है। जो कि 1 मई 2025 से प्रभावशील है। परिवहन के दौरान एसओपी का उल्लंघन पाये जाने पर उद्योगों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। उमेश पटेल ने कहा कि प्रदूषण के रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया 1 अगस्त 2024 से प्रभावशील है तो आगे की प्रक्रिया में आठ माह की देर कैसे हुई। चौधरी ने कहा कि कुल 49 शिकायतें थीं, जिन पर कार्यवाही की गई। 6 लाख 90 हजार की पैनाल्टी ठोंकी गई।

उमेश पटेल ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को किसी मामले की शिकायत होती है, उसका समाधान 16 दिसंबर 2025 में जाकर होता है। अधिकारी धोखा दे रहे हैं। अभी भी फ्लाई ऐश वैसे ही पड़े हैं। गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? चौधरी ने कहा पिछली सरकार की तुलना में हम कई गुना ज्यादा कार्यवाही कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि आप समय बरबाद कर रहे हैं।

रायबरेली सांसद ने वायनाड में खुद बताई पूरी कहानी

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच क्यों हो गई अनबन?

नई दिल्ली/ एजेंसी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी से अनबन की कहानी साझा की है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फिर से कैसे दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू हुई और इस सुलह में प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड का क्या कुछ योगदान था। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो साझा किया है। जिसमें वह अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में एक दिलचस्प किस्से को साझा कर रहे

हैं। राहुल ने बताया कि वायनाड ने भाई-बहन के बीच के गतिरोध को किसी भी शांति वार्ता से कहीं ज्यादा तेजी से सुलझा दिया था। साझा किए गए वीडियो में राहुल गांधी 2024 के वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के लिए पार्टी द्वारा बनाए जा रहे घरों के शिलान्यास समारोह में बोल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राजनीति में अपने 22 वर्षों पर विचार करते हुए तर्क दिया कि राजनेताओं को अपने बारे में अधिक खुला और पारदर्शी होना चाहिए। राहुल ने कहा कि मैं 2004 से राजनीति में हूं, तकरीबन 22 साल बीत चुके हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, चीजों के बारे में सोचने का आपका तरीका बदलने लगता है। उन्होंने कहा कि एक बात जिस पर मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं वह यह कि राजनेताओं को अपने बारे में अधिक खुलकर बोलना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर का बजट आपको आईएमएफ से मिले पैकेज से भी ज्यादा

नई दिल्ली। यूएनएचआरसी के 61वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। 25 फरवरी को हाई-लेवल सेगमेंट के दौरान 'राइट टू रिप्लाई' का उपयोग करते हुए भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान लगातार झूठा प्रचार कर रहा है और उसकी बयानबाजी में निराशा व ईर्ष्या झलकती है। उन्होंने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1947 में जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पूर्णत: वैध और अंतिम था।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मिली बड़ी राहत

हाई कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक;ब्रह्मचारी को तगड़ा झटका

नई दिल्ली/ एजेंसी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को राहत देते हुए झूंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज कथित यौन उत्पीड़न के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में मामले में अगली सुनवाई तक जबरदस्ती कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मिली गिरफ्तारी से राहत मिलना, केस दर्ज कराने वाले रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि बटुकों के साथ

कथित यौन शौषण के आरोप में शंकराचार्य के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद वाराणसी में मठ में जश्न मनाया गया। शंकराचार्य ने अपने भक्तों और छोटे बच्चों को गुलाल लगाकर इस मौके को उत्सव की तरह मनाया और त्योहार की खुशी में शामिल हुए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती केस में एंटीसिपेटरी बेल पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस हुई। इसमें राज्य सरकार और शिकायतकर्ता के वकीलों ने एंटीसिपेटरी बेल का विरोध किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफसे सीनियर वकीलों ने दलीलें पेश कीं। उनकी तरफ से शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी के क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी दी गई।

शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत

अरविंद को कोर्ट ने किया रिहा,सीबीआई को लगाई फटकार

नई दिल्ली/ एजेंसी

आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में पार्टी के शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में न केवल केजरीवाल और सिसोदिया, बल्कि विजय नायर समेत सभी 23 आरोपियों को भी सभी आरोपों से मुक्त किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सीबीआई इस मामले में किसी भी तरह की 'आपराधिक साजिश' या 'आपराधिक मंशा' को साबित करने में विफल रही। फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने इसे 'सत्य की जीत' बताया और कहा कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसे न्यायपालिका ने विफल कर दिया। इस निर्णय ने आम आदमी पार्टी की साख को मजबूती दी और राजनीतिक माहौल में बड़ी हलचल मचाई। अदालत के फैसले की बाद सीबीआई के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है क्योंकि जांच के कई पहलुओं को या तो नज़रअंदाज़ कर दिया गया है या उन पर ठीक से विचार नहीं किया गया है। सीबीआई इस फैसले को तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी। इस मामले में बरी किए गए दूसरे आरोपियों में

कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह धाल, अर्जुन पांडे, बुचिबाबू गोरंटला, राकेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, चनप्रीत सिंह रायत, अरविंद कुमार सिंह, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी. सरथ चंद्र रेड्डी शामिल हैं। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सीबीआई की जांच की कमियों पर नाराज़गी जताई और कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सिसोदिया के खिलाफ भी कोई पहली नज़र में केस नहीं बनता है। सीबीआई पिछली आप सरकार की एक्साइज पॉलिसी से जुड़े करप्शन केस की जांच कर रही है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सख्त टिप्पणी की कि डिटेल्ड चार्जशीट में कई कमियां थीं, जिनकी सबूतों या गवाहों से पुष्टि नहीं हुई। चार्जशीट में अंदरूनी विरोधाभास कॉन्सपिरेसी थ्योरी को कमजोर करते हैं। केजरीवाल के खिलाफ आरोप बिना किसी सबूत के टिक नहीं सकते। कोर्ट ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया है। जज ने कहा कि यह कानून के खिलाफ है। सिसोदिया के बारे में जज ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि वह इसमें शामिल है।

शिव शक्ति से ऊपर कोई नहीं-पत्नी सुनीता?

आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बड़ी कानूनी और राजनीतिक जीत लेकर आया है। बहुचर्चित दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से ससम्मान बरी कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष किसी भी प्रकार के आपराधिक इरादे को साबित करने में विफल रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सभी 23 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि जब दस्तावेजों और बयानों को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक प्रशासनिक विचार-विमर्श था। कोर्ट ने माना कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई आपराधिक इरादा नहीं था और अभियोजन पक्ष न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरा।

संक्षिप्त समाचार

आर.टी.ई. के तहत प्रवेश के लिए सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक

महासमुन्द (समय दर्शन)। महासमुंद नगर के नयापारा नोडल क्षेत्रांतर्गत आने वाले आरटीई के तहत प्रवेश के लिए जो लोग आवेदन करना चाहते हैं। वह अपना दस्तावेज सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी अमी रूफस प्राचार्य स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तुमाडबरी स्थित भवन में 31 मार्च के पूर्व अनिवार्य रूप से जमा करें। जिससे निर्धारित समय पर सत्यापन किया जा सके ,स्वामी आत्मानंद नोडल के अंतर्गत आने वाले स्कूल हैं मां गायत्री हायर सेकेंडरी स्कूल, वृंदावन इंग्लिश स्कूल, एम विद्या मंदिर, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, श्याम विद्या मंदिर, डायरेक्शनल इंग्लिश स्कूल, द न्यू होली फेथ स्कूल महासमुंद के अंतर्गत अध्ययन - अध्यापन हेतु प्रमाण पत्र की सत्यापन हेतु, मूल प्रति अनिवार्य है तथा दस्तावेज के अभाव में सत्यापन नहीं हो पाएगा और उनका आवेदन लॉटरी के लिए पात्र नहीं होगा। उक्त जानकारी संस्था के मीडिया प्रभारी व्याख्याता हरीश पाण्डेय ने दी है।

दिग्विजय महाविद्यालय के गौरव बने उज्ज्वल कसेर, पत्रकारिता परीक्षा में हासिल किया प्रथम स्थान

राजनांदगांव जिले में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने एक बार फिर जिले में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। हाल ही में घोषित तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणामों में विभाग के छात्र उज्ज्वल कसेर ने जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 85 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। उल्लेखनीय है कि दिग्विजय महाविद्यालय जिले का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पत्रकारिता का पाठ्यक्रम संचालित होता है, और यहां के विद्यार्थियों ने सदैव शैक्षणिक गुणवत्ता का परिचय दिया है। उज्ज्वल की इस सफलता के साथ ही उर्वशी साहू (83 प्रतिशत) और काजल चंद्राकर (82 प्रतिशत) ने क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त कर विभाग की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयां दी हैं।

अपनी इस विशिष्ट उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए उज्ज्वल कसेर ने विभाग की अध्यक्ष डा. बीएन जागृत व प्राध्यापकों अमितेश सोनकर, रेशमी साहू और विभा सिंह के प्रति हृदय से आभार प्रकट किया और अपनी सफलता का पूरा श्रेय उनके कुशल मार्गदर्शन व प्रेरणादायी शिक्षण को दिया।

छत्तीसगढ़ में आरटीई विवाद : शिक्षा मंत्री के बयान पर सवाल, विशेषाधिकार हनन की मांग

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव द्वारा शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून को लेकर दिया गया बयान विवादास्पद हो गया है। अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह के सवाल पर मंत्री ने सदन में कहा कि आरटीई के तहत अब केवल कक्षा पहली में प्रवेश दिया जा रहा है और नर्सरी में भर्ती बंद कर दी गई है, क्योंकि यह कानून 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लागू नहीं होता। छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने मंत्री के बयान को भ्रामक बताया और इसे आरटीई कानून की गलत व्याख्या करार दिया। श्री पॉल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर मंत्री के खिलाफविशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरटीई कानून की धारा 12 (1) (ग) स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि कोई निजी स्कूल पूर्व-प्राथमिक (नर्सरी/केजी) कक्षाएं संचालित करता है, तो वहां भी 25 प्रतिशत सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। अभिभावक संगठन का कहना है कि एक ओर विभाग स्वयं 5 वर्ष के बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश की अनुमति दे रहा है, वहीं मंत्री 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कानून लागू नहीं होने की बात कह रहे हैं। यह स्थिति स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी है। पॉल ने चेतावनी दी है कि यदि नर्सरी स्तर पर आरटीई प्रवेश बंद हुआ, तो हजारों गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे निजी स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा के अपने कानूनी अधिकार से वंचित रह जाएंगे।

वैचारिक चेतना का नवोदय : पंडित दीनदयाल उपाध्याय महा-प्रशिक्षण अभियान कार्यशाला संपन्न

महासमुंद(समय दर्शन)। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में रविवार को 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय महा-प्रशिक्षण अभियानङ्क 2026' के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला वैचारिक जागरण और संगठनात्मक नवसंकल्प का सशक्त मंच बनकर उभरी। यह आयोजन केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि विचारों के पुनरुत्थान और कार्यकर्ता चेतना के नवोदय का प्रतीक सिद्ध हुआ।

कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष दीपक मस्के, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी एवं डॉ विमल चोपड़ा विषय वक्ता के रूप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

मुख्य वक्ता अखिलेश सोनी ने पार्टी की संघर्षमयी यात्रा का स्मरण कराते हुए कहा कि दो सांसदों से प्रारंभ हुआ यह वैचारिक कारवां आज 200 से अधिक सांसदों के विराट जनसमर्थन तक पहुंचा है। यह विस्तार केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में समर्पित कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम है। उन्होंने संगठन की विचारधारा, कार्यशैली और नेतृत्व की प्रतिबद्धता को मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक सुदृढ़ रूप से स्थापित करने का आह्वान किया।

सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने प्रशिक्षण के विषयों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें इतिहास और विकास की यात्रा, सैद्धांतिक अधिष्ठान, एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पंचनिष्ठा, कार्यकर्ता विकास, वर्तमान राष्ट्रीय चुनौतियां तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे विविध आयामों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रशिक्षण संगठन को नई दिशा और नई शक्ति प्रदान करेगा।

दीपक मस्के ने ्द्ब सोशल मीडिया सरल अप के बारे में विस्तार से वक्तव्य दिया.अपने प्रेरक वक्तव्य में कहा कि पार्टी के सिद्धांत और सरकार की जनहितैषी योजनाएं तभी सार्थक होंगी, जब वे जन-जन तक संवेदनशीलता और समर्पण के साथ पहुंचें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सेवा, संवाद और समन्वय को अपना मूलमंत्र बनाने का आह्वान किया।

डॉ.विमल चोपड़ा ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्र के समग्र उत्थान के लिए पंच परिवर्तन की भावना को जीवन में उतारना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व परिवर्तन के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति को सुदृढ़ करे। परिवार प्रबोधन के अंतर्गत परिवारों में भारतीय संस्कार, संवाद और मूल्यों को मजबूत करना जरूरी है। सामाजिक समरसता का भाव विकसित कर जाति-भेद से ऊपर उठकर एकात्मता स्थापित करनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण को जीवन का अनिवार्य कर्तव्य मानते हुए प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता अपनानी चाहिए। साथ ही स्वदेशी को बढ़ावा देते हुए अपने नागरिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है।

जिलाध्यक्ष येतराम साहू ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि यह महा-प्रशिक्षण अभियान संगठन की आत्मा को और अधिक प्रखर बनाने का प्रयास है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांतों से अनुप्राणित यह अभियान कार्यकर्ताओं को वैचारिक दृढ़ता, संगठनात्मक अनुशासन और सामाजिक संवेदनशीलता के साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा नए कलेवर और नवचेतना के साथ राजनीति को सेवा और राष्ट्रनिर्माण का माध्यम बनाने की दिशा में अग्रसर है।

कार्यक्रम में महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, बीज विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोगरा पटेल, पूर्व राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक प्रीतम दीवान पूर्व विधायक त्रिलोचन पटेल पूर्व विधायक परेश बागबाहरा विपिन उपवेजा प्रदीप चंद्राकर सतपाल सिंह पाली जिला के विषय वक्ता एवं सभी मंडल के विषय वक्ता एवं जिला पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष मोर्चा अध्यक्ष के उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम का संचालन महामंत्री थान सिंह दीवान एवं जितेंद्र त्रिपाठी द्वारा किया गया आभार राहुल चंद्राकर के द्वारा किया गया। वक्त जानकारी आनंद साहू जिला मीडिया प्रभारी प्राप्त हुआ।

आयरन स्पंज की चोरी करने, अवैध रूप से परिवहन एवं खपाने वाले को पकड़ने में बसना महासमुंद पुलिस को मिली सफलता

महासमुन्द एस पी प्रभात कुमार के निर्देशन व बसना थाना निरीक्षक शरद दुबे की सूझबूझ से अवैध स्पंज आयरन चोरी व परिवहनकर्ता पुलिस के हत्थे चढ़े

दो ट्रक व करीब 22 लाख रुपयो के 68.755 मिट्रिक टन अवैध स्पंज आयरन जप्त

कुल जप्त सम्पत्ति कीमत करीब 42 लाख रुपये।

फर्जी, कूटरचित दस्तावेजो के द्वारा अवैध लोहे को वैध दिखाने रच रहे थे साजिश

रंजित सिंह नाम का ड्राइवर हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों को लालच देकर थोड़ा-थोड़ा लोहा, कम दाम में करता था खरीदी व अवैध भंडारण

बसना (समय दर्शन)। थाना बसना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेसी4585 व सीजी 07 एवी 5290 से संदिग्ध रूप से स्पंज आयरन को उड़ीसा से रायपुर परिवहन किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर बसना पुलिस द्वारा तत्काल जाँच कार्यवाही शुरू की गयी, इस दौरान ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेसी 4585 के चालक सोनूलाल मोंगरे पिता निरगुन मोंगरे साकिन लांती थाना सिंघोड़ा जिला महासमुन्द एवं ट्रक क्रमांक सीजी 07 एवी 5290 में चालक रामेश्वर मानिकपुरी पिता अघनदास मानिकपुरी साकिन वार्ड नं दो सरायपाली थाना सरायपाली जिला महासमुन्द से पूछताछ कर दोनो ट्रकों की तलाशी ली गई। दोनों ट्रकों में स्पंज आयरन लदा होना पाया गया उक्त आयरन स्पंज के संबंध में दस्तावेज मांगने व पुछताछ करने पर उपलब्ध बिल के आधार पर ट्रक में लदा स्पंज आयरन फर्म जय भोले इस्पात रायगढ़ पुसौर से लोड कर उरला रायपुर ले जाने के संबंध में जानकारी ट्रक चालक द्वारा दी गई।

दिया गए जानकारी व प्रस्तुत दस्तावेज में भिन्नता होने पर ट्रक चालको द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से संदेह प्रतीत होने पर दस्तावेजों की गहन जांच पड़ताल किया गया। तकनीकी रूप से जांच करने पर ज्ञात हुआ की ट्रक में लदा स्पंज आयरन को लोहराचट्टी से रंजित सिंह पिता रामेश्वर सिंह निवासी लोहराचट्टी थाना सोहेला जिला बरगढ़ उड़ीसा के द्वारा लोहराचट्टी उड़ीसा स्थित उसके गोदाम से लोड किया गया है।

ट्रक ड्राइवर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर ट्रक ड्राइवर ने बताया की रंजीत सिंह निवासी लोहाराचट्टी द्वारा अवैध लाभ अर्जन करने की मंशा से राष्ट्रीय राजमार्ग में स्पंज आयरन का परिवहन करने वाले विभिन्न ट्रक चालकों को लाभ अर्जन करने का झांसा देकर ट्रक चालकों को प्रवंचित कर उनसे थोड़ा-थोड़ा स्पंज आयरन कम कीमत में खरीद कर चोरी एव छल से क्रय कर लेता था और उन स्पंज आयरन को अपने गोदाम में अवैध भंडारन कर फ़र्ज़ी कुट रचित बिल बनवाकर स्पंज आयरन का परिवहन लोहराचट्टी जिला बरगढ़ उडिसा से रायपुर उरला में विक्रय करने हेतु परिवहन करते थे।

स्पंज आयरन का अवैध भंडारन व फ़र्ज़ी कुटरचना का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 318(4),316(4),317(2),336(2) ,338,340,3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

संपूर्ण कार्यवाही थाना बसना पुलिस द्वारा किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी- 1- सोनूलाल मोंगरे पिता निरगुन मोंगरे साकिन लांती थाना सिंघोड़ा जिला महासमुन्द छ.ग.।

2- रामेश्वर मानिकपुरी पिता अघनदास मानिकपुरी साकिन वार्ड नम्बर दो, सरायपाली थाना सरायपाली जिला महासमुन्द छ.ग.।

3- रंजित सिंह पिता रामेश्वर सिंह साकिन लोहरा चट्टी थाना सोहेला जिला बरगढ़ उडिसा।

जप्त संपत्ती- 1 ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेसी 4585 एवं स्पंज आयरन 37.730 मैट्रिक टन, कीमत 12 लाख रूपया एवं परिवहन में प्रयुक्त ट्रक का मूल्य 10 लाख रुपये।

2- ट्रक क्रमांक सीजी 07 एवी 5290 एवं स्पंज आयरन 31.025 मैट्रिक टन, कीमत 10 लाख रूपया एवं परिवहन में प्रयुक्त ट्रक का मूल्य 10 लाख रुपये।

भक्ति गीतों और ढोल-नगाड़ों की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए

दुर्ग में निकली पहली बार फाल्गुन एकादशी को बाबा श्याम की ऐतिहासिक निशान ध्वज यात्रा

दुर्ग । छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी दुर्ग में पहली बार फाल्गुन एकादशी को प्रदेश की सबसे बड़ी निशान यात्रा निकाली गयी जिसमें 1300 श्याम प्रेमियों से अधिक ने निशान ध्वज उठाया। दुर्ग में निशान यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिला। निशान यात्रा श्री सत्तीचौरा मां दुर्गा मंदिर गंजपारा से कादम्बरी नगर स्थित श्री श्याम मंदिर तक निकाली गई। निशान यात्रा के पहले दुर्गा मंदिर में बाबा श्याम की ज्योत ली गयी, एवं पूजा अर्चना करके श्याम बाबा की महाआरती की गयी, तथा पुष्पांजलि कराई गय। आयोजन समिति के प्रमुख योगेन्द्र शर्मा बटी ने बताया कि निशान यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्याम ध्वज लेकर शामिल हुए और पदयात्रा की। नगर में भाव विभोर होकर लोगों ने पदयात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान निशान यात्रा में बाबा की झलक पाने के लिए राहगीर भी लालायित हो रहे थे। श्री श्याम मंदिर में निशान चढ़ाते हुए भक्तों ने श्याम बाबा के दर्शन किए

दुर्ग में पहली बार 1300 से अधिक धर्मप्रेमियों की निशान यात्रा को देखने एवं फूलों की वर्षा करने अलग अलग स्थानों में धर्मप्रेमी जमा हुए, इस निशान यात्रा में नगर की सैकड़ों महिलाओं सहित युवा श्रद्धालु लाल, पीले ध्वज निशान लेकर भक्तगण श्याम गुणगान करते हुए शामिल हुए। साथ ही श्री श्याम जी की आकर्षक चलित झांकी, बाबा का रथ बग्गी राधा कृष्ण जी बनी हुई झांकी घोड़ा बग्गी भी निशान यात्रा में निकाली गई।

पद यात्रा कर निशान चढ़ाने को लेकर मान्यता यह रही है कि श्री श्याम बाबा के महाबलिदान शीश दान के लिए उन्हें निशान चढ़ाया जाता है। यह उनकी विजय का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने धर्म की जीत के लिए दान में अपना शीश ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था। जिन्हें प्रसन्ना करने निशान छोटे से बड़े मुख्यत केसरी नीला , सफेद ,लाल या पीले रंग का झंडा निशानों पर श्याम बाबा और कृष्ण भगवान के जयकारे और दर्शन के फोटो लगाते है। वही कुछ निशानों पर नारियल और मोरपंख भी लगाया जाता है। जिससे श्याम सरकार सभी के हर बिगड़े कार्य बना देते है व भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए सभी भक्त श्याम मंदिरों में अपनी मन्नाते मांगते हुए निशान चढ़ाते हैं।

सत्तीचौरा दुर्गा मंदिर से निशान लेकर जब श्याम प्रेमी निकले तब पूरे रास्ते मे श्याम बाबा की जय, हारे का सहारा श्याम हमारा की गूंज पूरे शहर में रही, जगह जगह निशान यात्रा का स्वागत किया गया, आतिशबाजी फूलों की बरसात एवं बाबा के अमृत रंगों की वर्षा की गई.

निशान चढ़ाने की परंपरा और मन्नत का संबंध- मान्यता है कि खाटू श्याम बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए पूरे साल यहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। जो भी अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में आता है, वह मन्नत मांगता है। मन्नत पूरी होने पर भक्त निशान चढ़ाने की प्रतिज्ञा करते हैं। खाटू श्याम निशान यात्रा में कई ऐसे श्रद्धालु मिलते हैं जो बताते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हुई, इसलिए वे ध्वज लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। कोई संतान सुख मिलने पर आया है, तो कोई बीमारी से राहत मिलने पर। कुछ लोग हर साल निशान चढ़ाते हैं, चाहे मन्नत हो या न हो।

बंटी शर्मा ने बताया कि लगभग 1300 धर्मप्रेमियों की निशान यात्रा जोकि लगभग 800 मीटर लंबी थी, यात्रा दुर्गा मंदिर से शनिचरी बाजार, गांधी चौक, सदर बाजार, मोती काम्प्लेक्स, इंदिरा मार्किट, स्टेशन रोड, धमधा ओवर ब्रिज के ऊपर से कादम्बरी नगर श्री श्याम मंदिर पहुँची, जहाँ बाबा की नजर उतार कर स्वागत किया गया..

मानव जनकल्याण संस्थान छत्तीसगढ़ की संवेदनशील पहल

15 वर्षीय दिव्यांग बालक यदुराम बारिया को प्रदान की गई व्हीलचेयर, जीवन है अनमोल अभियान के माध्यम से समाज सेवा की नई मिसाल

सरायपाली (समय दर्शन)। मानवता और करुणा का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मानव जनकल्याण संस्थान छत्तीसगढ़ की टीम ने आज सरायपाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत राजाडीह में एक विशेष सेवा कार्य संपन्न किया। संस्था द्वारा 15 वर्षीय दिव्यांग बालक यदुराम बारिया, जो शारीरिक रूप से चल-फिर पाने में असमर्थ हैं, को व्हीलचेयर प्रदान की गई। यह पहल संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विजय कुमार चतुर्वेदी की पहल और मार्गदर्शन में संपन्न हुई।

यदुराम बारिया पिछले कई वर्षों से शारीरिक असमर्थता के कारण घर तक सीमित जीवन जीने को मजबूर थे। आर्थिक परिस्थितियाँ भी ऐसी नहीं थीं कि परिवार स्वयं व्हीलचेयर की व्यवस्था कर सके। जब यह जानकारी मानव जनकल्याण संस्थान की टीम तक पहुँची, तो संस्था ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायता का निर्णय लिया। आज व्हीलचेयर प्राप्त करते ही यदुराम और उनके परिजनों की आँखों में जो खुशी और आशा की चमक दिखी, वह इस सेवा कार्य की सबसे बड़ी उपलब्धि रही।

इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों ने संस्था के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्य समाज में विश्वास और सहयोग की भावना को सशक्त बनाते हैं।

समाज सेवा के विविध आयामों में सक्रिय संस्था - कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विजय कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि मानव जनकल्याण संस्थान छत्तीसगढ़ एक समाजसेवी, समुदाय आधारित संगठन के रूप में निरंतर कार्यरत है। संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ग्राम उत्थान, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, नशामुक्ति, दिव्यांगजन सहयोग एवं शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक करने और उनका लाभ प्राप्त करने समग्र विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रही है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि वर्तमान में महासमुंद जिले में संस्था द्वारा जीवन है अनमोल नामक अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्महत्या जैसी दुखद घटनाओं की रोकथाम करना है। यह अभियान लोगों को मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए समर्पित है। संस्था का मानना है कि हर जीवन मूल्यवान है और समय पर संवाद, मार्गदर्शन एवं सहयोग से कई जिंदगियाँ बचाई जा सकती हैं।

डॉ. चतुर्वेदी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि यदि किसी भी प्रकार की शासकीय या व्यक्तिगत समस्या हो, तो वे निसंकोच संस्था से संपर्क कर सकते हैं। संस्था सदैव जनहित में तत्पर है और जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रामीणों ने रखीं अपनी समस्याएँ - कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएँ भी रखीं। कई ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से उन्हें विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ परिवारों ने यह भी बताया कि वे पात्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं।

ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए डॉ. विजय कुमार चतुर्वेदी ने आश्वासन दिया कि वे संबंधित उच्च अधिकारियों से इस विषय में चर्चा करेंगे और समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे अपनी समस्याओं का लिखित आवेदन मानव जनकल्याण संस्थान छत्तीसगढ़ के कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि संस्था व्यवस्थित रूप से संबंधित विभागों तक उनकी बात पहुँचा सके।

सेवा और संवेदना का संगम - आज के इस कार्यक्रम में संस्था की टीम से सविता साहू, कौशल्या बरिया, श्रवण निराला सहित अनेक ग्रामीणजन उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर यह संदेश दिया कि समाज में बदलाव सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

यदुराम बारिया को प्रदान की गई व्हीलचेयर केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि उनके लिए नई संभावनाओं का द्वार है—स्कूल जाने की उम्मीद, समाज से जुड़ने का अवसर और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक सशक्त कदम।

मानव जनकल्याण संस्थान छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची सेवा वही है, जो जरूरतमंद के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाए। संस्था की यह पहल न केवल सरायपाली क्षेत्र, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायी उदाहरण है।

मुख्यधारा की ओर बढ़ते कदम – पुनर्वासित युवाओं ने विधानसभा में देखी जनतांत्रिक प्रक्रिया

नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे पुनर्वासित युवा: विधानसभा में समझी जनतांत्रिक प्रणाली

रायपुर। माओवाद की विचारधारा त्यागकर संविधान की राह अपनाने वाले 120 पुनर्वासित युवाओं के दल ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचकर जनतांत्रिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। युवाओं ने सदन की कार्यवाही को करीब से देखा तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझा। विधानसभा का यह शैक्षणिक भ्रमण उनके लिए प्रेरणादायी और मार्गदर्शक अनुभव साबित हुआ।

विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आत्मीय मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी का 'जय जोहार' के साथ स्वागत करते हुए कहा कि पुनर्वास का निर्णय लेने वाले सभी साथियों का राज्य सरकार हृदय से अभिनंदन करती है। उन्होंने कहा कि सरकार पुनर्वासित युवाओं की सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सभी पुनर्वासित युवा समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें और आत्मनिर्भर बनें। इसी उद्देश्य से पुनर्वास नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंसा का मार्ग छोड़कर आज संविधान के मंदिर में खड़े होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का साक्षी बनना इस बात का प्रमाण है कि बदलाव संभव है। मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं को शिक्षा, स्वरोजगार और शासन की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि जो युवा 'गन'तंत्र का रास्ता छोड़कर गणतंत्र की मुख्यधारा में लौटे हैं, उनका राज्य सरकार हृदय से स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि संविधान का मार्ग ही शांति, विकास और समृद्धि का मार्ग है। राज्य सरकार पुनर्वासित युवाओं के सम्मानजनक जीवन, रोजगार और कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनेंगे और अन्य लोगों को भी मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक श्री किरण देव तथा श्री सुशांत शुक्ला ने भी पुनर्वासित युवाओं से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि शासन उनके साथ दृढ़ता से खड़ा है। पुनर्वासित युवाओं ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को निकट से देखने का यह अवसर उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायी रहा। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि वे अब संविधान और कानून के दायरे में रहकर समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उल्लेखनीय है कि 120 सदस्यीय इस दल में 66 पुरुष एवं 54 महिला प्रतिभागी शामिल हैं। पुनर्वासित युवाओं का यह समूह तीन दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के तहत रायपुर पहुंचा है, जहां वे शासन-प्रशासन की विभिन्न व्यवस्थाओं, कार्यप्रणालियों एवं विकासात्मक पहलों से अवगत हो रहे हैं।

स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक अधोसंरचना की दिशा में प्रदेश का सशक्त संकल्प है सिटी गैस परियोजना

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सीएनजी युक्त वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रायपुर नगर निगम की पहली पाइपलाइन गैस उपभोक्ता श्रीमती पूनम चौबे से संवाद कर घरेलू उपयोग में पाइपलाइन गैस की सुविधा के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर रजत जयंती वर्ष मना रहा है और इन वर्षों में प्रदेश ने विकास के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। सिटी गैस अवसंरचना परियोजना इस विकास यात्रा में एक नई उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल नई सुविधा नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक अधोसंरचना की दिशा में प्रदेश का सशक्त संकल्प है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब मेट्रो शहरों की तर्ज पर डीपीएनजी (डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस) के माध्यम से घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पाइपलाइन से गैस उपलब्ध होगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को रिफिलिंग की झंझट से मुक्ति मिलेगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सस्ती और सुलभ ऊर्जा मिलने से उद्योग क्षेत्र को भी गति मिलेगी तथा प्रदेश में निवेश की संभावनाएं सशक्त होंगी। मुख्यमंत्री ने एचसीजी समूह को बधाई देते हुए अपेक्षा व्यक्त की कि वे रायपुर सहित बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले में शीघ्र ही सीएनजी स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि वाहनों में सीएनजी के उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी और आम नागरिकों के ईंधन खर्च में भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रस्तुत राज्य बजट में अधोसंरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हों और प्रदेशवासियों को मेट्रो शहरों जैसी सुविधाओं का अनुभव हो। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलें, इस दिशा में सरकार ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे स्वच्छ ईंधन अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में सहभागी बनें और हरित, विकसित एवं आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान दें। उल्लेखनीय है कि सिटी गैस अवसंरचना परियोजना रायपुर, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से घरेलू उपयोग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों हेतु पाइपलाइन द्वारा पीएनजी की आपूर्ति की जाएगी तथा वाहनों के लिए सीएनजी भी उपलब्ध होगा।

राज्यपाल के गोद ग्राम पंचायत बिजली के ग्रामीणों ने किया लोकभवन का भ्रमण

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज अपने गोद ग्राम बिजली, जिला गरियाबंद से आए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गांव में चल रहे विकास कार्यो की प्रगति के बारे में ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनके कार्यालय को अवगत कराएं।

राज्यपाल के गोद ग्राम बिजली के ग्रामीण बहुत खुश नजर आए। उनकी आत्मीयता को देखकर ग्रामीण भावुक हो उठे और कहा कि राज्यपाल जी से उन्हें बहुत अपनत्व मिलता है। उनके गांव के विकास के लिए सभी ग्रामीणों ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। सरपंच श्रीमती पदमा निषाद ने बताया कि राज्यपाल जी के द्वारा उनके ग्राम पंचायत में टिन शैड, वॉटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पीट, नाडेप इत्यादि का काम करवाया जा रहा है। उनके गांव में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र भी है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ङ्कक्च-त-क्रू-त) के तहत भी उनके गांव में काम हो रहा है। इसके अलावा स्कूल में स्मार्ट बोर्ड भी प्रदान किया गया है। जिससे बच्चों की शिक्षा में मदद मिल रही है। उप सरपंच श्री रोशन राम पटेल ने बताया कि राज्यपाल जी ने जब से उनके गांव को गोद लिया है उनके गांव को विकास की गति मिली है। जिसके लिए पूरे ग्रामीणों की ओर से राज्यपाल का धन्यवाद किया। बिजली ग्राम पंचायत से आए ग्रामीणों ने इस दौरान लोकभवन का भ्रमण किया और यहां के इतिहास के बारे में जानकारी ली। साथ ही लोकभवन के द्वारा उन्हें महंत घासीदास म्यूजियम का भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के उप सचिव सुश्री निधि साहू उपस्थित थी।

शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल आजीविका प्राप्त करना नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त कर पूरे समाज का विकास होना चाहिए-श्री रमेन डेका

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल आजीविका प्राप्त करना नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त कर पूरे समाज का विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवर्तन जीवन का नियम है और शिक्षा हमारे जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव लेकर आती है। अगर हम अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज में पीछे छूट रहे लोगों का जीवन सुधार पायें उनकी ज़िंदगी बेहतर बना पायें तो हमारा जीवन सफल होगा और इस अनमोल मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर पाएंगे।

दीक्षांत समारोह में 816 स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट विद्यार्थियों को उपाधियाँ और पदक प्रदान किए गए। शेल इंडिया की अध्यक्ष और शेल लुब्रिकेंट्स एशिया पैसिफिक की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंसी मदन त्रिपाठी को विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (ऑनोरिस काउसा) से सम्मानित किया गया।

राज्यपाल श्री रमेन डेका आज एमिटी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा से ही विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया का सकता है। उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिए ज्ञान का ज़िक्र करते हुए कहा कि हमें अपनी अंतर आत्मा से साक्षात्कार करते रहना चाहिए ताकि हम सही और ग़लत में अंतर समझ सकें। अंतरात्मा की सुनेंगे वो आपको कभी ग़लत काम करने नहीं देगी और इसी तरह आप खुद को ईश्वर के नज़दीक पायेंगे और आपको आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी। शिक्षा से हम ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए और हमें शिक्षा में भी एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमें हमें तकनीक का उपयोग करके जीवनशैली को बेहतर बनाना सिखाती है।

मुख्यमंत्री को धान से तौलकर प्रदेश के अन्नदाताओं ने जताया आभार

किसानों की समृद्धि और खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना होगा साकार: मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है और किसानों की समृद्धि और खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री से आज उनके निवास कार्यालय में प्रदेश के किसानों ने सौजन्य मुलाकात की और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से धान के अंतर की 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पूर्व किसानों के खातों में अंतरित करने की घोषणा पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री को धान से तौलकर प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सदैव किसानों की चिंता करते हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की उन्नति ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि अटल जी के समय किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की गई, जिससे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने लगा। इससे पहले किसानों को महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था, जिससे वे आर्थिक शोषण का शिकार होते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को ब्याज मुक्त पूंजी की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहा है और प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि धान के अंतर की लगभग 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पूर्व किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। 28 फरवरी को बिलासपुर जिले से इस राशि का अंतरण किया जाएगा और पूरे प्रदेश के विकासखंडों में इसे उत्सव की तरह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 25 लाख 24 हजार किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार आगे भी किसानों के हित में प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर सहित प्रदेश भर से आए किसान उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया 'गुलाल' होली विशेषांक का विमोचन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में 'गुलाल' होली विशेषांक का विमोचन किया। वरिष्ठ पत्रकार श्री जगजीत सिंह द्वारा प्रकाशित इस विशेषांक में होली पर्व के सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक पक्षों को समाहित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, भाईचारे और भारतीय परंपराओं की जीवंत अभिव्यक्ति का पर्व है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकाशन हमारी लोकसंस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने इस रचनात्मक पहल के लिए प्रकाशक और उनकी टीम को बधाई दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल, श्री दीपक विश्वकर्मा, श्री नदीम मेमन तथा श्रमजीवी गिल्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आर.के. गांधी उपस्थित थे।

मठपुरैना निवासी से लाखों की ठगी

रायपुर। महज 25 मिनट में अज्ञात ठग ने बैंक एकाउंट से 1.23 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। मठपुरैना ज्योतिनगर निवासी पुष्पेंद्र साहू ने कल शाम टिकरापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि 22 फरवरी को दोपहर 12.41 से 1.07 बजे के बीच अज्ञात एकाउंट होल्डर ने पुष्पेंद्र के खाते से 4 बार में 1.23 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। कल इसकी भनक लगने पर उसने 318-4 के तहत मामला दर्ज कराया। इसी तरह से पुलिस आरक्षक की पत्नी से साइबर ठगों ने ढाई महीने पहले 1.89 लाख रुपए ठग लिए।9563211900 नंबर के अज्ञात कालर ने 1 दिसंबर को दोपहर महिला को काल कर आनलाइन मार्केटिंग में डबल मुनाफे का झांसा दिया।- घर बैठे फायदे का काम समझ कर महिला झांसे में आकर उसके भेजे लिंक को क्लिक किया और ठग ने रकम ट्रांसफर कर लिया । जब मुनाफा नहीं मिला तो ठगे जाने का अहसास हुआ। यह रकम महिला के एसबीआई और पोस्ट आफिस के खाते से ट्रांसफर किया। सिविल लाइन थाने के पास कालोनी में रहने वाले आरक्षक मुकेश साहू ने आज दोपहर पत्नी के साथ हुई ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

रिटायर्ड आईएएस गणेश शंकर मिश्रा बने राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा को राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को लेकर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, गणेश शंकर मिश्रा का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगा और आगामी निर्देश जारी होने तक वे इस पद पर बने रहेंगे। उनकी नियुक्ति को राज्य की नीति निर्माण और विकास योजनाओं को नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण मंडल की कोरबा पॉवर लिमिटेड,पताड़ी के क्षमता विस्तार के लिए आयोजित जनसुनवाई हजारों लोगों की उपस्थिति में सफलता पूर्वक सम्पन्न

कोरबा: पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जिले के बरपाली तहसील अंतर्गत कोरबा पॉवर लिमिटेड (केपील),पताड़ी के प्रस्तावित 1600 मेगावाट के क्षमता विस्तार के लिए शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गई। कलेक्टर कोरबा द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्यावरण स्वीकृति के आदेश के लिए जनसुनवाई 27 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे से ग्राम सरगबूंदिया स्थित शासकीय स्कूल के खेल मैदान में आयोजित की गई। जिसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में कोरबा के अतिरिक्त कलेक्टर देवेन्द्र पटेल, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अंकुर साहू मौजूद थे। इसके साथ ही एसडीएम सरोज कुमार महिलांगे, कार्यपालक अभियंता श्री प्रसन्ना सोनकर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। अदाणी पॉवर लिमिटेड से पर्यावरण विभाग प्रमुख आर एन शुक्ला ने केपील परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जनसुनवाई लगभग 2.30 घंटे तक चली। जिसमें बरपाली तहसील के ग्राम खोड्डल, पताड़ी, सरगबूंदिया,पहंदा, बरीडीह, तिलकेजा इत्यादि सहित कुल 12 गांव के हजारों ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान सभा में ग्रामीणों द्वारा मुख्यरूप से क्षेत्र के विकास, नौकरी और स्वरोजगार के लिए उचित प्रबंध सहित कई बातों तथा सुझावों को पीठासीन अधिकारी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनकर कंपनी के अधिकारियों की उपस्थिति में संबंधित मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया। इस तरह जन सुनवाई में पधारे 95 फीसदी लोगों ने अदाणी पॉवर लिमिटेड के केपील की 800 मेगावाट की दो इकाईयों के क्षमता विस्तारण का समर्थन किया। लोक सुनवाई में उपस्थित सरपंचों में ग्राम पताड़ी के श्री प्रधान सिंह ठाकुर, सहित ग्राम पहंदा की श्रीमती संगीता कंवर, सरगबुंदिया के श्री अश्वनी कुमार तंवर, ढ़नढ़नी के श्री कन्हैय्या बिंझवार, खोड्डल की श्रीमती निकिता सिंह, संडैल की श्री उषा धनंजय बिंझवार, बरीडीह की श्रीमती रिंकी कंवर, कटबितला की श्रीमती अचला कंवर, ग्राम अखरापाली की श्रीमती गीता बाई मांझी, उरगा की श्रीमती ललिता बाई जगत, बरपाली के श्री भुनेश्वर बिंझवार तथा तिलकेजा की श्रीमती तेरस बाई सहित सभी ग्राम सचिव व हजारों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने समर्थन में अपनी बात रखी। इसके अलावा तिलकेज से किशन साव, भाजपा अखरापाली की जनपद सदस्य श्रीमती कमलेश्वरी कंवर व श्री अजय कंवर, कटबितला जनपद के पूर्व अध्यक्ष और बरपाली तहसील के अग्रवाल समाज के अध्यक्ष श्री किशन अग्रवाल भाजपा उरगा के मंडल अध्यक्ष किशन साव तथा भाजपा बरपाली के मंडल अध्यक्ष श्री राजू साहू ने कहा, कि केपील संयंत्र के क्षमता विस्तारण से क्षेत्र में विकास के नए आयाम खुलने के साथ ही हजारों लोगों को नई नौकरियां मिलने की संभावनाएं और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने की उम्मीद जताते हुए अपनी सहमति प्रदान करने की बात कही। रिसदिहापारा की एक महिला ग्रामीण श्रीमती भारती कुर्रे ने जनसुनवाई के दौरान कहा कि, ÷कोरबा पॉवर लिमिटेड के आने से हमारे गाँव में विकास के कई कार्य बड़ी ही तेज गति से संचालित हो रहे हैं। गांवों की सड़कें अब सोलर लाइट से जगमगाने लगी हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी शाला विकास के साथ साथ विद्यार्थियों को बैग सहित कापी, जेमेट्री बॉक्स इत्यादि भी बाँटे गए।

संपादकीय

सौदा पारदर्शी हो

बड़ी ताकतें अपनी कंपनियों को सौदा दिलवाने के लिए भारत को महज एक बाजार के रूप में देखती हैं। मगर भारत को उनके दबाव में नहीं आना चाहिए। यह भी जरूरी है कि सौदा पारदर्शी हो, ताकि उसको लेकर विवाद पैदा ना हो। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने का फैसला तत्कालीन यूपीए सरकार ने किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने उसे आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने खरीदारी की शर्तों में उलटफेर कर दी। इसी कारण मोदी सरकार ने जब पहली बार राफेल विमानों को खरीदा, तो उस सौदे पर ना सिर्फ भारत, बल्कि फ्रांस में भी बड़े विवाद हुए। दोनों जगहों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मगर वह दीगर मामला है। उस विवाद को विमानों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं माना जाएगा। हां, पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई भारतीय राफेल विमानों को मार गिराने का दावा किया था, तो जरूर विमानों की तत्परता से संबंधित प्रश्न उठे। बहरहाल, उस दावे की सच्चाई क्या है, इस बारे में भारत सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। इस बीच चार दिन के उस सीमित युद्ध ने भारत की रक्षा तैयारियों में और दम लगाने की जरूरत निर्विवाद रूप से जाहिर किया। यह भी साफ हुआ कि आगे की लड़ाइयों में वायु सेना की प्रमुख भूमिका होगी। अत: भारतीय वायु सेना की लड़ाकू विमानों की जरूरत को पूरा करना अनिवार्य है। अब केंद्र ने 114 राफेल विमानों को खरीदने का जो फैसला किया है, उसे इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फ्रेंच कंपनी दसॉ के राफेल विमान उन्नत तकनीक से लैस हैं, यह आम धारणा है। चूंकि भारत के पास पहले ये विमान हैं, इसलिए उन्हें ही खरीदना भी सही निर्णय माना जाएगा। अब समझ यह बनी है कि आधुनिक हथियार एवं उपकरण उच्च तकनीक से संचालित हैं, वैसे में एक जैसे सिस्टम अधिक कारगर हो रहे हैं। इसलिए भारत को अलग-अलग देशों से सिस्टम खरीदने की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। बड़ी ताकतें अपनी कंपनियों को सौदा दिलवाने के लिए भारत जैसे देशों को महज एक बाजार के रूप में देखती हैं। मगर भारत को उनके दबाव में नहीं आना चाहिए। उसे अपनी जरूरतों के अनुरूप सौदे करने चाहिए। फिर यह भी जरूरी है कि हर सौदा पारदर्शी हो, ताकि उसको लेकर उस तरह का संदेह पैदा ना हो, जैसा पिछले राफेल सौदे के समय हुआ था।

बच्चों को सोशल मीडिया के असर से बचाने की जरुरत

अजीत द्विवेदी

देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सम्मेलन चल रहा है। एआई के आर्थिक, सामरिक इस्तेमाल और उसके असर की व्याख्या हो रही है। दुनिया भर के विशेषज्ञ दिल्ली में हैं। और इसके समानांतर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कैसे बचाया जाए। जब से ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है और सभी सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी बच्चे का अकाउंट उनके प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए तब से भारत और दुनिया भर के देशों में इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है। भारत में आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से इसकी पहल हो रही है कि 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से कैसे दूर रखा जाए। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के टेम्पलेट का इस्तेमाल करके यहां भी पाबंदी लगाई जाए। इसके साथ ही इस प्रतिबंध के असर को लेकर भी बहस छिड़ गई है। यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया पर पाबंदी बच्चों को इसके असर से बचाने का रामबाण उपाय है? इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाबंदी का समर्थन और विरोध करने वाले दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया के असर से बचाने की जरुरत है। बचाने के तरीके को लेकर जरूर मतभेद हैं। अमेरिका और यूरोप में कुछ दिन पहले हुए सर्वेक्षणों से पता चला कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जेन जेड यानी 1997 से 2013 के बीच जन्मे बच्चे अपने से पहले वाली पीढ़ी यानी मिलेनियल्स के मुकाबले कम बुद्धिमान हैं। यह पहली बार है, जब कोई पीढ़ी अपने से पिछली पीढ़ी से कम बुद्धिमान हैं और इसका मुख्य कारण स्मार्ट फोन या दूसरे स्मार्ट गैजेट्स और सोशल मीडिया है। टेलीविजन को भी इडियट बॉक्स कहते थे लेकिन उसने बच्चों के सोचने, समझने की क्षमता को उतना प्रभावित नहीं किया, जितना इंटरनेट से कनेक्टेड गैजेट्स और सोशल मीडिया ने किया है। सोचें, इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि की वजह से दुनिया संज्ञानात्मक क्रांति (कॉग्निटिव रिवोल्यूशन) के मध्य में है और दूसरी ओर संचार क्रांति ने एक पूरी पीढ़ी की बुद्धिमता छीन ली है! क्या कृत्रिम बुद्धिमता के फलने फूलने के लिए जरूरी है कि प्राकृतिक बुद्धिमता का क्षरण हो? बहरहाल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ बच्चों और किशोरों की संज्ञानात्मक क्षमता को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी सामाजिकता और मानसिक व शारीरिक क्षमता को भी प्रभावित कर रहे हैं। बच्चे और किशोर निराशा और अवसाद का शिकार हो रहे हैं। उनके अंदर कुंठा बढ़ रही है और सामाजिकता कम होती जा रही है। वे अपनी एक दुनिया रचने लगे हैं और कई बार यह उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले ही दिनों दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तीन बहनों के आत्महत्या करने की खबर आई थी। उनको सोशल मीडिया की ऐसी लत लगी थी कि वे अपनी वास्तविक दुनिया से बेखबर हो गईं थीं और एक आभासी दुनिया में रहने लगी थीं, जिसकी परिणति तोनों की मृत्यु में हुई। लेकिन क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने और बच्चों व किशोरों को स्क्रीन एडिक्शन यानी फोन व सोशल मीडिया की लत से बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाए? ध्यान रहे कोई भी पाबंदी बहुत खराब आर्थिक नीति मानी जाती है लेकिन यह सिर्फ आर्थिक नीति का मामला नहीं है, बल्कि इसके दूसरे पक्ष भी हैं। उन सबको ध्यान में रख कर ही कोई भी प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें भेड़चाल के लिए कोई जगह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदी लगा दी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी टिकटॉक से लेकर, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए पाबंदी लगाने की योजना का ऐलान किया है।

मुफ्त रेवड़ी संस्कृति जीवंत लोकतंत्र के लिये घातक

ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र की विडंबना यह है कि चुनाव आते ही जनसेवा का स्वरूप बदलकर जनलुभावन राजनीति में परिवर्तित हो जाता है। राजनीतिक दलों ने मुफ्त की योजनाओं को चुनावी सफलता का शॉर्टकट बना लिया है। मतदाताओं को तात्कालिक आर्थिक लाभ देकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति लगातार मजबूत हो रही है। आगामी तीन-चार माह में विधानसभा चुनाव होने है, इसी संदर्भ में जब असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुईं, तब इस संस्कृति का प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसी पृष्ठभूमि में देश की शीर्ष अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, ने मुफ्त की योजनाओं के अनियंत्रित विस्तार पर गंभीर टिप्पणी की। यह टिप्पणी केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को लेकर एक चेतावनी है। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं। लेकिन जब जनहित और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समस्या जन्म लेती है। लक्षित समर्थन और अतिरेक उदारता में अंतर है। एक ओर ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, दूसरी ओर ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल मतदाता को तात्कालिक राहत देकर उसे निर्भरता की आदत सिखाती हैं। जब राजस्व घाटे से जूझ रहे राज्य मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा या नकद वितरण की घोषणाएं करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि यह संसाधन कहां से आएंगे और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? राजकोषीय अनुशासन किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत का आधार है। यदि राज्य अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए खजाने को खाली करता है, तो दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। जो धन बुनियादी ढांचे के निर्माण, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण, विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार और रोजगार सृजन में लगना चाहिए, वह वोटों की फसल काटने में खर्च हो जाता है। यह प्रवृत्ति केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी चिंताजनक है। लोकतंत्र में मतदाता की स्वतंत्रता सर्वोपरि मानी जाती है। यदि मतदाता को परोक्ष रूप से आर्थिक प्रलोभन देकर प्रभावित किया जाता है, तो यह स्वतंत्र निर्णय की भावना को कमजोर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने तार्किक प्रश्न उठाया कि राज्य रोजगार सृजन और कौशल विकास पर अधिक ध्यान क्यों नहीं देते? वास्तव में रोजगार ही स्थायी सशक्तीकरण का माध्यम है। जब व्यक्ति अपने श्रम और कौशल से आय अर्जित करता है, तब उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं। इसके विपरीत, निरंतर मुफ्त सुविधाएं व्यक्ति को निर्भर बनाती हैं। धीरे-धीरे परिश्रम की संस्कृति कमजोर पड़ती है और समाज में अकर्मण्यता की मानसिकता पनपने लगती है। यह स्थिति लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सक्रिय और जिम्मेदार नागरिकता का नाम है। चुनाव पूर्व घोषित योजनाओं की निष्पक्षता भी प्रश्नों के घेरे में है। जब आचार संहिता लागू रहने के दौरान बड़े पैमाने पर आर्थिक वितरण होता है, तो विपक्षी दल इसे असमान प्रतिस्पर्धा मानते हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष निगरानी की जिम्मेदारी भारत का निर्वाचन आयोग पर आती है। निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी दल मतदाताओं को अप्रत्यक्ष रिश्वत देकर चुनावी लाभ न ले। आचार संहिता का उल्लंघन केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन है। यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो भविष्य में यह प्रवृत्ति और गहरी जड़ें जमा सकती है। निस्संदेह, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि राज्यों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की खास तौर से देखभाल करें। हालांकि, जब राजस्व घाटे वाले राज्य मुफ्त की योजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, तो सरकारी खजाने पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है। विडंबना यह है कि जिस धनराशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम बनाने और शिक्षा की सुविधा को समृद्ध करने के लिये किया जाना चाहिए, वो राशि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये खर्च कर दी जाती है। जरूरत इस बात की है कि कौशल विकास के जरिये लोगों को इस तरह सक्षम बनाया जाए जिससे उन्हें दीर्घकालिक व स्थायी लाभ मिल सकें।

यह भी समझना होगा कि मुफ्त योजनाओं का हर स्वरूप गलत नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में राहत देना, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय सहायता पहुंचाना, सामाजिक न्याय के तहत वंचित वर्गों को अवसर देना-ये सब राज्य की जिम्मेदारी है। परंतु चुनावी मौसम में अचानक घोषणाओं की बाढ़ आ जाना और दीर्घकालिक वित्तीय परिणामों की अनदेखी करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत नहीं है। यह राजनीतिक दलों के वैचारिक दिवालियेपन को दर्शाता है, जहां दूरदृष्टि की जगह तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्र की मजबूती केवल संस्थाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों की सजगता से भी आती है। यदि मतदाता केवल तात्कालिक लाभ देखकर मतदान करता है, तो वह अनजाने में ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करता है जो अंतत: उसी के भविष्य को प्रभावित करती है। परिपक्व मतदाता वही है जो घोषणाओं के पीछे की मंशा और आर्थिक व्यवहार्यता को समझे। वह यह पूछे कि पांच साल बाद राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, विकास की दिशा क्या होगी और रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे। लोकतंत्र में वोट केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है।

आज भारत स्वयं को वैश्विक मंच पर एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। हम विश्वगुरु बनने का संकल्प लेते हैं, लेकिन यदि हमारी राजनीति लोकलुभावनवाद के जाल में उलझी रहेगी, तो यह संकल्प खोखला सिद्ध होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव तभी सार्थक है जब हमारी नीतियां दूरदर्शी, संतुलित और टिकाऊ हों। मुफ्त की संस्कृति से बाहर निकलकर उत्पादकता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। यह समय आत्ममंथन का है। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि जनता को सशक्त बनाना केवल धन बांटने से संभव नहीं है। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार-ये चार स्तंभ किसी भी राष्ट्र की मजबूती तय करते हैं। यदि इन पर निवेश बढ़ेगा, तो नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे और राज्य पर बोझ कम होगा। वहीं, नागरिकों को भी यह ठानना होगा कि वे तात्कालिक प्रलोभनों के बजाय दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देंगे। लोकतंत्र की सुदृढ़ता तभी सुनिश्चित होगी जब शासन और जनता दोनों अपने-अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें।

निस्संदेह, चुनावी निष्पक्षता के लिये यह आवश्यक हो गया है कि चुनाव से पहले घोषित की गई या लागू की गई लोकलुभावनी नीतियों व योजनाओं की गहन पड़ताल की जाए। विपक्षी दलों द्वारा बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया था कि पिछले साल अक्तूबर में आचार संहिता लागू रहने के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 15,600 करोड़ रुपये दिए गए थे। जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध कदम था। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपरोक्ष रूप से रिश्वत देने के प्रयासों पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही इस दिशा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में कार्रवाई भी करनी चाहिए। निर्विवाद रूप से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना हमारे जीवंत लोकतंत्र के लिये हानिकारक है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। यह कार्य करने की मानसिकता को बाधित करती है और समाज में सरकार-निर्भरता एवं अकर्मण्यता की संस्कृति को जन्म देती है। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो आर्थिक असंतुलन और राजनीतिक अविश्वास दोनों बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि नीतियों की पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और चुनावी निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यही लोकतंत्र की वास्तविक रक्षा है, यही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।

भारत में एपस्टीन फाइल्स की चर्चा क्यों?

डॉ. नीरज भारद्वाज

मीडिया में पिछले कई दिनों से एपस्टीन फाइल्स का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। एपस्टीन फाइल्स नाम अपने आप में चौंका देने वाला है। लोग इसके फेटो, इसके कामकाज, शैली और इसके अंदर दिखाए जाने वाले कुकर्मों पर चर्चा कर रहे हैं। चारों तरफ भय का वातावरण बना दिया गया है। विश्व के लगभग सभी बड़े चेहरे इसमें दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों का यह काला सच है। अमेरिका और बहुत से यूरोपीय देशों में सेक्स की बात होना साधारण सी बात हो सकती है क्योंकि ओपन सेक्स और खुला व्यापार वहां की नीति का हिस्सा है लेकिन छोटे-छोटे बच्चों को मारना, उनका माँस खाना, उनका यौन उत्पीड़न करना आदि इंसानियत के नाम पर काला धब्बा है।

अब चलते हैं भारतीय जीवन शैली की ओर। भारतीय जीवन शैली अध्यात्म से जुड़ी हुई है. यह आत्मा के मुक्त होने की साधना पर चलती है। यहां आवागमन के चक्कर से मुक्ति का सबसे बड़ा काम होता है। भारतीय सनातन संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो यहां भोगवादी संस्कृति नहीं बल्कि आध्यात्मिक संस्कृति का सबसे बड़ा काम होता है। यहां पर तीज-त्यौहार, व्रत इतने हैं कि लोग उन्हीं में अपने जीवन की व्यवस्था और व्यस्तता को रखते हैं। सुयोग्य वर या वधू के लिए सोलह सोमवार का व्रत करना(भगवान शिव की आराधना करना), ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए युवा मंगलवार का व्रत करते हैं और अपने साधन तथा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। एकादशी को कितने ही स्त्री-पुरुष व्रत करते हैं। ज्येष्ठ मास में तो निर्जला एकादशी का व्रत, जब सूर्य अपने ताप पर होता है और वहां जल के बिना जीव का रहना, कितनी बड़ी साधना का काम है। इसके साथ जब हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो आप देखेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग पूरे दिन पानी तक नहीं पीते और रात्रि 12:00 बजे या चंद्रमा के दिखाई देने पर ही अपने व्रत को चरणामृत तथा फ्ल आदि खाकर खोलते हैं। इतने बड़े संकल्प सिद्धि के इस देश में भोगवादी संस्कृति कहां टिकने वाली है। कल्पवास के समय भी प्रयागराज में लोग महीना भर अपना घर त्याग कर, व्रत कर के, बहुत से समाधि पर बैठ जाते हैं। बहुत से कल्पवास में एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। यह सब पारिवारिक लोग हैं जो परिवार की व्यवस्था में हैं। यह व्रत और तीज-त्योहार का पालन पारिवारिक लोग ही कर रहे होते हैं। जब करवा चौथ की बात होती है तो अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए महिलाएं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती, चंद्रमा को देखकर ही व्रत को खोलती हैं। छठ मईया का व्रत तो पूरी रात जल में खड़ा रहना और सूर्योदय के साथ उसको खोलना है । यह व्रत कई दिनों तक चलता है। इसके साथ और भी बहुत सारे व्रत और तीज-त्योहार जुड़े हुए हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत भी माताएं करती हैं। संतोषी मां का भी व्रत करती हैं। बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार का व्रत भी करते हैं यानी कि भारतीय संस्कृति में व्रत की महिमा है। खाने-पीने या भोग की प्रवृत्ति न होकर अन्न-जल और विषय वस्तुओं को त्याग कर एक साधारण जीवन जीने की बहुत बड़ी सार्थकता है। आंकड़े बताते हैं कि सन 2025 प्रयागराज के महाकुंभ में लगभग साठ करोड़ लोगों ने स्नान किया।

यह सारी बातें जो हो रही हैं, यह सब पारिवारिक लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं जबकि संत समाज की यदि हम बात करें तो वह ज्ञान का प्रकाश पुंज हैं। अध्यात्म, दर्शन, भक्ति, योग, साधना आदि के सच्चे साधक सभी साधु, संत, महात्माओं को सादर प्रणाम। यह हम सब सामान्य लोगों को दिव्य ज्ञान देते हैं। संत हम सब लोगों को इस भौतिक या भोगवादी युग से दूर ले जाकर आध्यात्मिक चिंतन की ओर जोड़ते हैं। हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, कथाएं आदि वैश्विक ज्ञान परंपरा में अग्रणीय हैं। कथाओं के अंदर त्याग ही त्याग है, आत्म शुद्धि है। आत्म शुद्धि के साथ-साथ आवागमन के चक्कर से मुक्ति है।

हम यहां भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि और कर्म प्रधान समाज में कर्म करते हुए, आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं जबकि इसके दूसरी ओर यदि आप यूरोपीय या अमेरिका के अन्य देशों की बात करें तो वहां पर अध्यात्मवादी नहीं बल्कि भोगवादी संस्कृति आप देखोगे, वहां सेक्स का खुलापन है। वहां कपड़े पहनना ना पहनना, एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ, पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ, अपने संबंध स्थापित कर लेता हैं। ऐसे ही वहां संतान उत्पत्ति हो भी रही है। परिवार के प्रति बहुत कम लोगों का रुझान देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग तो शादी ही नहीं करते बल्कि अपनी दैहिक भूख मिटाने के लिए बाजार का सहारा लेते हैं। सही मायनों में यही एपस्टीन फाइल्स हैं । इन देशों में देह बाजार में बिकती है, लोग उपभोग की वस्तु का मूल्य देकर सुख भोग लेते हैं।इन देशों में हर चीज बाजार है। हर वस्तु का भोग ही भोग है। मनुष्यता के नाम पर भी नर-नारी के बीच के संबंधों को ज्यादा महत्ता नहीं देते। यदि एक ऐसी फाइल्स अमेरिका और यूरोप के लोगों को लेकर खुलती है, जिसमें सेक्स के माध्यम से अलग-अलग देशों के बड़े-बड़े धनपति और उद्योगपति दिखाई देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है।

दूसरी ओर शोर मच रहा है कि वहां पर कम उम्र के बच्चों के साथ यौवन शोषण हो रहा था। वह उन देशों की विडंबना है। वह किस तरीके से उन सब संबंधों को देखते-समझते रहते हैं, यह उनकी समझ है। माना कि बच्चों के साथ यौन शोषण होना किसी भी हद तक ठीक नहीं है। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इनकी पद, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान सभी कुछ इनसे ले लेना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय परिवेश अर्थात सनातन संस्कृति में ऐसी चर्चाओं को करके हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या हम भी इस ओर बढ़ रहे हैं? भारतीय लोगों की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। अपवाद तो हर जगह मिल ही जाते हैं।

विचार करें तो जितने भी आक्रांता और आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को ही तो तोड़ा। हमारे आचार-विचार, सामाजिक व्यवस्थाओं को भंग किया। समाज में अस्थिरता पैदा की, अपने धर्म का प्रचार-प्रसार किया। समाज को खंड-खंड कर दिया। चारों ओर भय का वातावरण पैदा किया गया। इतना कुछ होने के बाद भी हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार,पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर जीवित रहे। यह जरूर कहा जा सकता है कि समय के प्रवाह के साथ कुछ एक अपवाद जरूर रह जाते हैं। अब कुछ एक लोग ऐसी प्रवृत्ति के यहाँ भी देखे जा सकते हैं लेकिन पूरी समाज व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता है।

इसके साथ ही एक ओर बात भी यहां सोची-समझी जा सकती है। आज पूरा विश्व आर्थिक कमजोरी की स्थिति में फंसा हुआ है। पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में उपनिवेशवाद को लेकर युद्ध हुआ, अब उपनिवेशवाद नहीं है अर्थात कोई किसी का गुलाम देश नहीं है। विश्व के बड़े देश बाजार को साधने में लगे हुए हैं। सभी अपने वर्चस्व को बचाने के लिए लगे हुए हैं। विश्व चारों तरफ युद्ध के माहौल से जूझ रहा है। इसमें यूरोपीय देश और अमेरिका यह सब वैश्विक मंदी से डर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में विश्व का ध्यान युद्ध, डॉलर की टूटती हुई कीमतें, उद्योग और वहां के व्यापार में हो रहे घाटे को देखते हुए विश्व का ध्यान भंग करने के लिए अमेरिका और अन्य देश मिलकर ऐसी चर्चा को विश्व में जीवित करना चाह रहे हैं जिससे कि विश्व का ध्यान उन सब बातों से हट जाए। डी डॉलराइजेशन, वहां की मार्केट में क्राइसिस आना, उद्योगपतियों का उसे देश के प्रति ध्यान हटना आदि, एशियाई देशों का वर्चस्व बढ़ना, व्यापारियों का वहां खर्च करना, नए उद्योग-धंधों का शुरू करना आदि भी इन देशों को खटक रहा है। वहां डर का माहौल बना हुआ है, इस डर के माहौल से उबरने के लिए अमेरिका, उसके सहयोगी देश या वहां की सरकार ऐसे खुलासे दुनिया के सामने रख देना चाहती है। लोगों का ध्यान भंग हो जाएगा और वह यहीं उलझ कर रह जाएंगे तथा अपना काम निकालने की सोच रहे हैं जबकि यह सारी घटना या इन फाइल्स के जो भी कार्य हैं, वह बहुत साल पुराने हैं और कुछ ताजा भी हैं । लोग इतिहास को भूल जाते हैं. जरा इस ओर भी नजर दौड़ाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इन देशों में ऐसा सभी कुछ होता रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों अर्थात सोवियत, अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रेंच की सेनाओं द्वारा जर्मनी में लगभग 400,000 कब्जे के बच्चे (Occupational children/Besatzungskinder) पैदा हुए थे जिन्हें अक्सर उस समय नाजायज या युद्ध के बच्चे माना जाता था। इन बच्चों के पिता विदेशी सैनिक थे और इनमें से लगभग 3 लाख बच्चे केवल सोवियत संघ की रेड आर्मी से संबंधित थे। ऐसी कितनी ही घटनाएं गिनाई जा सकती हैं। इसे आप क्या कहेंगे? इन देशों का वास्तविक चेहरा यही है. निर्णय आपको लेना है।

भाजपा को लेने के देन पड़ेंगे

हरिशंकर व्यास

क्या भाजपा राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कराने और जीवन भर चुनाव लड़ने से रोकेगी? ऐसे ही क्या प्रियंका गाधी वाड्रा की भी सदस्यता खत्म कराने की पहल होगी? भाजपा की ओर से पहले राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की चर्चा थी लेकिन उसको पता है कि उसमें पार्टी को शामिल होना होगा। यह भी सवाल था कि अगर सरकार के नीतिगत फैसलों की आलोचना के लिए विपक्ष के किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाने लगे तो फिर यह बात बहुत दूर तक चली जाएगी। तभी पार्टी के एक सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सबस्टेंसिव मोशन पेश कराया गया।

ध्यान रहे पहले सबस्टेंसिव मोशन पर यूपीए की पहली सरकार ने कई सांसदों की सदस्यता समाप्त की थी। उनके ऊपर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप लगे थे। बाद में कमीशन लेकर एमपी फंड बेचने के आरोप में भी इस तरह का प्रस्ताव लाया गया। लेकिन राहुल गांधी का मामला अलग है। राहुल एक तो नेता विपक्ष हैं और दूसरे देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई बहुत मजबूत आधार नहीं है। फोर्ड फाउंडेशन से संबंध या जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध रखना सदस्यता खत्म करने का आधार नहीं हो सकता। तभी ऐसा लग रहा है कि भाजपा सांसद की ओर से पेश किया गया प्रस्ताव का इस्तेमाल राहुल को डराने और दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर है। राइट विंग इकोसिस्टम के लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर राहुल की सदस्यता चली जाती है तो प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगी। अगर ऐसा होगा तो पार्टी के अंदर पावर सेंटर बदल जाएगा। यानी इस तरह से राहुल से पीछा छूटने की भाजपा के नेता उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है।

वैसे भाजपा नेताओं का एक समूह प्रियंका के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष के कई सांसद स्पीकर के चैंबर में चले गए थे। उन्होंने वहां गाली गलौज की। यह भी कहा गया कि विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे। दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसकी साजिश रची थी और उनके उकसाने पर ये सांसद स्पीकर के कक्ष में गए थे। इस आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात है।

परंतु क्या भाजपा सचमुच ऐसा कर पाएगी? यदि ऐसा किया तो राजनीति पर उसका क्या असर होगा? ध्यान रहे पिछली लोकसभा के कार्यकाल में सूरत में मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई थी। लोकसभा सचिवालय ने तत्काल उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। उनका तुगलक लेन का बंगला खाली करने को कहा गया। राहुल ने तत्काल बंगला खाली किया। बाद में ऊपरी अदालत ने सजा पर रोक लगा दी तो राहुल की सदस्यता भी बहाल हुई। उसके बाद फिर उनको वही बंगला आवंटित हुआ लेकिन वे उसमें रहने नहीं गए। अंत नतीजा क्या हुआ? बाद में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़ कर 99 हो गईं।

संक्षिप्त-खबर

बजट में जनआंकक्षाओं के साथ छलावा : विवेक वासनिक

राजनांदगांव। राजगामी संपदा न्यास के पूर्व अध्यक्ष विवेक वासनिक ने बजट को जनआंकक्षाओं के साथ छलावा बताते हुए कड़ी आलोचना की है। इसमें युवा, गरीब, किसान, मध्यमवर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए प्रावधान महज आंकड़ों का झूठा पुलिंदा है, जो हकीकत की धरातल में नहीं उतर पाएंगे। पिछले बजट में किए गए प्रावधानों का ही अब तक क्रियान्वयन नहीं होने से जनता में निराशा है ऊपर से वित्त मंत्री ने ऐसा बजट पेश किया है, जिसका जनता और प्रदेश के विकास से दूर दूर तक सरोकार नहीं है। कागजी आंकड़ों को पेश कर जनता को गुमराह कर रोजी, रोजगार, निर्माण, मूलभूत सुविधाएं जैसे मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया है।

बजट में आम जनता, किसान, मजदूर और युवाओं के लिए कोई ठोस नीति नहीं : भुनेश्वर बघेल

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक भुनेश्वर बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को केवल कागजों तक सीमित और निराशाजनक बताया। भुनेश्वर बघेल का कहना था कि इस बजट में आम जनता, किसान, मजदूर और युवाओं के लिए कोई ठोस नीति नहीं है, बल्कि यह महज आंकड़ों तक सिमटा हुआ है। पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए न तो कोई स्पष्ट कार्ययोजना दिखती है और न ही आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। कर्जमाफी, सिंचाई संसाधनों के विस्तार और कृषि लागत कम करने जैसी आवश्यक योजनाओं पर भी बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। महंगाई को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई ने आम जनता को परेशान कर दिया है, लेकिन बजट में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके अलावा मजदूर वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी कोई विशेष योजना की घोषणा नहीं की गई है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। युवाओं के मामले में भुनेश्वर बघेल ने कहा कि बजट में रोजगार सृजन और सरकारी भर्तियों के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं। यह केवल सामान्य घोषणाओं तक सीमित रहा है, जबकि युवाओं को ठोस अवसरों की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे पर भी उन्होंने निराशा व्यक्त की। उनका कहना था कि लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए बजट में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है। अंत में भुनेश्वर बघेल ने कहा कि यह बजट विकास के मामले में पूरी तरह विफल रहा है। आम जनता की उम्मीदों पर खरा न उतरने वाला यह बजट पूरी तरह से घोषणात्मक और निराशाजनक है।

पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय पेंटा में संजय कुमार मंडल ने संभाला प्राचार्य पद

सुकमा। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय पेंटा में 30 जनवरी 2026 को संजय कुमार मंडल ने विधिवत रूप से प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने विद्यालय के श्याम कुमार रामावत, पीजीटी गणित से पदभार लिया। उनके आगमन से विद्यालय परिवार में नई ऊर्जा और शैक्षणिक उत्कृष्टता को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं।

श्री मंडल ने 12 वर्षों तक जवाहर नवोदय विद्यालय दंतेवाड़ा जैसे अति दुर्गम एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सेवाएं दीं। इसके बाद 11 वर्षों तक जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। स्वैच्छिक स्थानांतरण के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय उज्जैन में पदस्थ हुए, जहां लगभग तीन माह की सेवा के बाद उप प्राचार्य पद पर पदोन्नत होकर पुन: डोंगरगढ़ में पदस्थापित हुए। उन्होंने दो वर्ष तक नारायणपुर जैसे अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2024-26 तक डोंगरगढ़ में सेवाएं देने के बाद अब वे पेंटा, सुकमा-1 में पदस्थ हुए हैं। विद्यालय में पदभार ग्रहण करने के 30 दिनों के भीतर ही उनके मार्गदर्शन में अकादमिक एवं संरचनात्मक स्तर पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। विद्यार्थियों और पालकों में भी उत्साह का वातावरण है। श्री मंडल ने अपने सेवाकाल में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। वर्ष 2004-07 में सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्ट परिणाम हेतु नवोदय विद्यालय समिति द्वारा गुरु श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किए गए। इसके अलावा वर्ष 2007 में सांसद बलिराम कश्यप, 2009 में उच्च शिक्षा मंत्री हेमचंद्र यादव, 2010 में मंत्री केदार कश्यप द्वारा एनएसएस में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित हुए। वर्ष 2017 में जिलाधीश मुकेश बंसल द्वारा जेएनवीएसटी में सर्वोत्तम पंजीकरण, 2020 में विधायक इंद्रशाह मंडावी, 2021 में विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू तथा 2024 में एसडीएम ओरछा द्वारा भी सम्मान प्राप्त किया।

प्रत्येक विकासखंड में आज दोपहर 12 बजे से होगा वृहद किसान सम्मेलन

महासमुंद(समय दर्शन)। जिले के सभी विकासखंडों में कल दोपहर 12 बजे से वृहद किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कृषि उपज मंडी प्रांगणों में आयोजित इस सम्मेलन में किसानों को धान खरीदी का अंतर राशि प्रदान की जाएगी साथ ही किसानों को शासन की विभिन्न कृषि योजनाओं, नवीन तकनीकों, बीज एवं उर्वरक प्रबंधन, फसल विविधीकरण तथा बाजार सुविधाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी।

कृषि उपसंचालक ने बताया कि 28 फरवरी को सभी विकासखंड मुख्यालयों में अलग-अलग स्थानों पर सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

महासमुंद विकासखंड में महासमुंद कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित सम्मेलन में योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक महासमुंद मुख्य अतिथि होंगे। बागबाहरा विकासखंड के बागबाहरा कृषि उपज मंडी प्रांगण में चंद्रहास चंद्राकर, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड तथा पिथौरा विकासखंड के पिथौरा कृषि उपज मंडी प्रांगण में येतराम साहू, जिला अध्यक्ष भारत स्काउट एंड गाइड मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसी तरह बसना विकासखंड के बसना कृषि उपज मंडी प्रांगण में डॉ. संपत अग्रवाल, विधायक बसना मुख्य अतिथि होंगे ।

इसी प्रकार सरायपाली विकासखंड के सरायपाली कृषि उपज मंडी प्रांगण में रूपकुमारी चौधरी, सांसद महासमुंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। सम्मेलन के दौरान किसानों को आदान सामग्री वितरण उन्नत कृषि तकनीक, आधुनिक उपकरणों के उपयोग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि ऋण, बीज वितरण एवं विपणन व्यवस्था संबंधी विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जिला कार्यसमिति घोषित, मीडिया प्रभारी बने वरिष्ठ पत्रकार जीवन साहू

भाजपा कार्यकर्ताओं सहित शुभचिंतकों ने दी बधाई

गरियाबंद (समय दर्श न)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू की अनुमति तथा जिला संगठन प्रभारी अमित चिमनानी एवं जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर की सहमति से पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष शोभाचंद पात्र ने जिला कार्यसमिति की घोषणा कर दी है। जिसमें गरियाबंद के वरिष्ठ पत्रकार जीवन एस साहू को जिला मीडिया प्रभारी बनाया गया है। श्री साहू पत्रकारिता के साथ ही समाजहित में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाते हुए आ रहे हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा में मीडिया प्रभारी का दायित्व मिलने पर उन्हें वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू, राजिम विधायक रोहित साहू, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय, पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी, जिला महामंत्री डॉ. आशीष शर्मा, चंद्रशेखर साहू, वरिष्ठ भाजपा नेता मुरलीधर सिन्हा, भाजपा कोषाध्यक्ष अजय रोहरा, प्रवक्ता पारस ठाकुर, राधेश्याम सोनवानी, मंत्री डॉ. मनीष सिंहा, भाजपा मीडिया सह प्रभारी रितेश यादव, मंडल अध्यक्ष सुमित पारख, मंडल अध्यक्ष धनराज विश्वकर्मा, अजजा मोर्चा उपाध्यक्ष तरुण ठाकुर, धनंजय नेताम सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने बधाई दी है।

संगठन को मिलेगी नई ऊर्जा- कार्यसमिति के गठन में संगठन ने संतुलन और समन्वय का विशेष ध्यान रखा है। इसमें वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ ऊर्जावान युवाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि अनुभव और उत्साह का बेहतर तालमेल स्थापित हो सके। यह नई टीम संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के साथ ही जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। नई कार्यसमिति के गठन से संगठन को मजबूती मिलने के साथ ही आगामी कार्यक्रमों और अभियानों को गति मिलेगी।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत की गई 16 चालानी कार्रवाही

महासमुंद(समय दर्शन)। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के निर्देशन में विकासखंड बागबाहरा अंतर्गत आंवराडबरी एवं भीमखोज में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग के संयुक्त प्रवर्तन दल के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) के तहत चालानी कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई डीपीएम श्रीमती नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन व जिला नोडल अधिकारी एन टी सी पी डॉक्टर छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से किया गया। कार्यवाही में औषधि निरीक्षक अवधेश भारद्वाज द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में आने वाले विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध, 06 अ नबालिको के तंबाकू उत्पाद के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध व धारा 06 ब शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध के अन्तर्गत कुल 16 चालान काटे गए। चालानी कार्रवाई में औषधि निरीक्षक अखिलेश पांडेय, अवधेश भारद्वाज एवं पुलिस विभाग से आरक्षक रेस कुमार दीवान उपस्थित थे।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने की पीएम आवास, मनरेगा, बिहान एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यों की विस्तृत समीक्षा

महात्मा गांधी नरेगा, पी एम आवास लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश

मनरेगा में 15 मार्च तक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र लगाने के निर्देश

जांजगीर-चांपा/समय दर्श न। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की जिला मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम भवन में विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बिहान योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत संचालित कार्यों की योजनावार प्रगति की जानकारी ली। जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महात्मा गांधी नरेगा, बिहान योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की ब्लॉकवार समीक्षा कर प्रगति तेज करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों को समय पर पीएम आवास उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य अपेक्षित गति से नहीं चल रहे हैं, उनके कार्यों में तेजी लाई जाए। आवास निर्माण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मनरेगा की समीक्षा के दौरान अधिक से अधिक श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाए। कार्यस्थलों पर पर्याप्त श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, मजदूरी का समय पर भुगतान करने तथा कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। महात्मा गांधी नरेगा में 15 मार्च तक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र लगाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लंबित निर्माण कार्यों की ब्लॉकवार समीक्षा कर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभान्वित करने तथा निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने कहा। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कार्यस्थलों पर पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित करने और मजदूरी का समय पर भुगतान करने पर करने के निर्देश दिए। साथ ही 15 मार्च तक सभी मनरेगा कार्यों में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने, अधिक से अधिक लेबर नियोजन करने तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

कलेक्टर ने बिहान योजना की समीक्षा करते हुए महिला स्व-सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों से जोड़कर सशक्त बनाने कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आजीविका गतिविधियों के तहत ऋण प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि हो। कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के सुचारू संचालन की समीक्षा की। ग्राम सभा के माध्यम से यूजर चार्ज वसूलने, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने तथा सेग्रीगेशन शेड के माध्यम से कचरे का पृथक्करण कर स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंच सके। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, जिला समन्वयक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

होली पर्व से पहले किसानों को मिलेगी खुशियों की सौगात

28 फरवरी को कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता होगी जारी

जिले के 118927 किसानों को मिलेंगे 450 करोड़ 85 लाख 45 हजार 132 रूपए

जांजगीर-चांपा / होली पर्व से पहले किसानों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 28 फरवरी को राज्य स्तरीय धान बोनस वितरण कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के 25 लाख 28 हजार से अधिक पंजीकृत किसानों को 10324 करोड़ रूपए आदान सहायता राशि का अंतरण करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री किसानों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी करेंगे।

उप संचालक कृषि ने बताया कि कृषक उन्नति योजना अंतर्गत जिले के 1 लाख 18 हजार 927 से अधिक पंजीकृत किसानों को 450 करोड़ 85 लाख 45 हजार 132 रूपए रूपये की आदान सहायता राशि सीधे कृषको के खाते में अंतरित किया जाएगा। इसके तहत जिले के समस्त विकासखण्डो में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विकासखण्ड नवागढ़ के तहत कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम भवन जांजगीर में प्रात: 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार विकासखण्ड बम्हनीडीह में जनपद पंचायत सभागार, विकासखण्ड पामगढ में सदभावना भवन, विकासखण्ड अकलतरा में जनपद पंचायत सभागार एवं विकासखण्ड बलौदा में जनपद पंचायत परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्किल द्वारा प्रथम ऑल इंडिया पोस्टल पैरा गेम्स 2025-26 का भव्य शुभारंभ

भिलाई। छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्किल द्वारा आयोजित प्रथम ऑल इंडिया पोस्टल पैरा गेम्स 2025-26 का भव्य उद्घाटन 27 फरवरी 2026 को प्रात: 9.00 बजे द एम्पायरियन होटल एंड रिसॉर्ट्स, भिलाई, दुर्ग में संपन्न हुआ। यह दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, जो भारतीय डाक विभाग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल है। इस आयोजन में टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम एवं शतरंज की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं। भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न डाक परिमंडलों से आए डाक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं।

उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. संजय तिवारी, माननीय कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग रहे। कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्यकर्ता अजय सिंह चौहान, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्किल, रायपुर रहे।

इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में गोकरन पाटिल, रिसाली, भिलाई, गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक (पैरों से पेंटिंग कर्ता) भी उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि डॉ. संजय तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण का माध्यम हैं, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और समावेशन की भावना को भी प्रबल करते हैं। उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों की सहभागिता को समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल छत्तीसगढ़ अजय सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्किल की समावेशी सोच और राष्ट्रीय स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के आयोजन डाक विभाग के कर्मचारियों में आपसी सौहार्द, टीम भावना और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। कार्यक्रम में निदेशक छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल दिनेश कुमार मिस्त्री ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा "vst All India Postal Para Games 2025-26 पर 4 picture PostCard का भी विधिवत विमोचन किया गया, जो इस ऐतिहासिक आयोजन की स्मृति को संजोने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उद्घाटन समारोह में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागी, डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, आयोजन समिति के सदस्य एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम खेल भावना, राष्ट्रीय एकता और दिव्यांग सशक्तिकरण के संदेश के साथ आगे बढ़ा।

संक्षिप्त समाचार

पाटन कालेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बढ़ावा हेतु क्रीयेटिव कार्नर की स्थापना

पाटन। शासकीय चंदूलाल चंद्राकार स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाटन में प्राचार्य डॉ नंदा गुरवारा के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित सामग्रियों के क्रीयेटिव कार्नर की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल, जनभागीदारी अध्यक्ष योगेश निक्की भाले, प्राचार्य डॉ नंदा गुरवारा द्वारा रीबन काटकर किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ नंदा गुरवारा ने अतिथियों को जानकारी देते हुए बताया कि महाविद्यालय में बांस शिल्प कला की कार्यशाला का आयोजन कर पाटन महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलाया गया ततपश्चात् यहाँ के छात्र छात्राओं ने बांस से विभिन्न उत्पादक सामग्रियों निर्माण किये है इसका प्रदर्शन क्रीएटिव कार्नर के रूप में अन्य छात्र छात्राओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। विद्यार्थियों द्वारा बनाये गए उत्पाद जैसे- मशरूम, साबुन, फिनाइल, बॉस से बने पानी की बॉटल, बैच, फ्लॉवर पॉट आदि बनाया गया है।जनभागीदारी अध्यक्ष योगेश निक्की भाले ने कहा कि विद्यार्थियों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकतानुसार हर सम्भव सहायता प्रदान की जायेगी । मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने प्राचार्य डॉ नंदा गुरवारा एवं छात्र छात्राओं की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों में कौशल विकास होने से अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सकते है। बांस से उत्पाद बनाने की रोजगार को शासन द्वारा लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवसर पर जनभागीदारी सदस्य, रामुराम चक्रधर, शत्रुहन देवांगन, सागर सोनी, आदित्य पाण्डेय, केवल देवांगन सहित अधिकारी कर्मचारी एवं छात्र छात्राये उपस्थित थे।
पाटन के विजय कांत बंछोर बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा दुर्ग के जिला सोशल मीडिया प्रभारी

पाटन क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है कि भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा दुर्ग की जिला कार्यसमिति में पाटन निवासी विजय कांत बंछोर को जिला सोशल मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है

पाटन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू जी के निर्देशानुसार तथा भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र कौशिक जी के अनुमोदन से यह नियुक्ति की गई है। विजय कांत बंछोर ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पार्टी की विचारधारा, नीति और जनहितकारी योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने का कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। इस नियुक्ति पर पाटन एवं दुर्ग जिले के कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है तथा उन्हें शुभकामनाएँ दी जा रही हैं।

जिला भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला योजना प्रचार प्रसार प्रमुख बने सेलूद के चंचल यादव

पाटन। भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी के मार्गदर्शन में, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक साहू जी निर्देश पर तथा संभाग प्रभारी श्री जगन्नाथ पाणिग्राही जी एवं जिला प्रभारी श्री नंदन जैन जी की सहमति एवं भाजपा जिला अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कौशिक जी के अनुमोदन से भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा दुर्ग के अध्यक्ष श्री तेखन सिन्हा ने चंचल यादव ग्राम सेलूद को जिला कार्यसमिति में जिला योजना प्रचार प्रसार प्रमुख बनाये जाने पर कार्यकर्ताओं के हर्ष व्यक्त किया है साथ ही साथ शीर्ष नेतृव को धन्यवाद ज्ञापित किया गया

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के 84,058 किसानों को मिलेगा धान बोनस, बिलासपुर से होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम

सारँगढ बिलाईगढ़- (समय दर्शन) विपणन वर्ष 2025 में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के 84058 किसानों ने अपना कुल 442948.84 मे.टन धान विक्रय किया जिसके अंतर राशि का भुगतान 28 फरवरी 2026 को "कृषक उन्नती योजना" के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा खेल मैदान, रहंगी, वि.ख. बिल्हा, जिला बिलासपुर से जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से 3237.96 लाख रुपये का हस्तांतरण करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के शुक्ला भवन, विशालपुर, रायपुर रोड़ सारंगढ़, जनपद पंचायत बरमकेला सभाकक्ष एवं जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के सभाकक्ष से कार्यक्रम के सीधा प्रसारण से जुड़ सकेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना: मजबूत हुई आजीविका की राह

जल संरक्षण के साथ ही ग्रामीण आजीविका संवर्धन का प्रभावी माध्यम

मुंगेली(समय दर्शन) जिले के विकासखण्ड लोरमी अंतर्गत ग्राम पंचायत औराबांधा में एक छोटी-सी पहल ने ग्रामीण आजीविका को नई दिशा दी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हितग्राही किसान किशन सिंह के खेत में निर्मित आजीविका डबरी आज जल संरक्षण, सिंचाई और मछली पालन का सशक्त माध्यम बन चुकी है। हितग्राही किशन सिंह ने बताया कि पहले सिंचाई के लिए पानी की कमी बनी रहती थी, लेकिन अब डबरी बनने से खेत में वर्षभर पानी उपलब्ध रहेगा और मछली पालन से आय भी बढ़ेगी।

जिले में कलेक्टर कुन्दन कुमार एवं जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय के मार्गदर्शन में आजीविका डबरी न केवल जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ग्रामीण आजीविका संवर्धन का भी प्रभावी माध्यम बन रहा है। योजना के तहत स्वीकृत 1.94 लाख रुपये की लागत से इस डबरी का निर्माण कराया गया। कार्य के दौरान कुल 792 मानव दिवस सृजित किए गए, जिससे स्थानीय मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिला और पलायन में कमी आई। निर्मित डबरी अब खेतों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। वर्षा जल संचयन और भू-जल रिचार्ज के माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित हुई है, जिससे खरीफ और रबी दोनों मौसमों में फसल उत्पादन की संभावना बढ़ी है। पहले जहां पानी की कमी के कारण फसल प्रभावित होती थी, वहीं अब किसान आत्मविश्वास के साथ बहुफसली खेती की ओर अग्रसर है।

साथ ही, डबरी में मछली पालन की योजना से अतिरिक्त आय का स्थायी स्रोत विकसित हो रहा है, जो परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रहा है। जिले में आजीविका संवर्धन की दृष्टि से आजीविका डबरी निर्माण की अभिनव पहल व्यापक स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2025-26 हेतु कुल 285 डबरी निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 218 कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और 20 पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष कार्यों को मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। यह पहल जल संरक्षण के साथ-साथ कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन को एकीकृत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ग्राफ्टेड बैगन से 16 लाख रूपए की आमदनी

उन्नत तकनीक से खेती कर किसान चिंतामणी ने बढ़ाई अपनी आमदनी

मुंगेली(समय दर्शन) किसान वैज्ञानिक पद्धति, उन्नत बीज और सही मार्गदर्शन के साथ खेती करें, तो कम भूमि में भी अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसी कड़ी में पथरिया विकासखंड के ग्राम करही के किसान चिंतामणि बंजारे ने नवाचार और आधुनिक तकनीक को अपनाकर खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया है। उन्होंने परंपरागत सब्जी खेती से आगे बढ़ते हुए उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में 10 एकड़ क्षेत्र में ग्राफ्टेड बैंगन की खेती कर लगभग 1100 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ। इस उत्पादन से उन्हें करीब 16 लाख रुपये की आमदनी हुई है।

कृषक चिंतामणी ने बताया कि सामान्य फसल की तुलना में ग्राफ्टेड बैगन में लागत अपेक्षाकृत कम आती है, जबकि उत्पादन अधिक मिलता है, परिणामस्वरूप आय दो से तीन गुना तक बढ़ जाती है। ग्राफ्टेड बैंगन की विशेषता इसकी मजबूत जड़ प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक उत्पादन है। पहले वे सामान्य सब्जियों की खेती करते थे, जिसमें लाभ सीमित और जोखिम अधिक था। किंतु उद्यान विभाग के प्रोत्साहन, तकनीकी सलाह और उन्नत पौध सामग्री के उपयोग ने उनकी खेती की दिशा ही बदल दी। उचित सिंचाई प्रबंधन, संतुलित उर्वरक उपयोग और नियमित देखभाल से फसल की गुणवत्ता बेहतर रही, जिससे बाजार में उन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त हुआ। आज वे आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, बल्कि अन्य किसानों को भी उन्नत तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ग्राफ्टेड बैंगन की खेती ने उनके परिवार की आय बढ़ाने के साथ-साथ गांव में आधुनिक कृषि की नई सोच को भी प्रोत्साहित किया है।

एसडीएम और डीएमसी ने पीएमश्री विद्यालयों का किया निरीक्षण

मुंगेली(समय दर्शन)केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी पीएमश्री योजना के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिले के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार मुंगेली एसडीएम अजय शतरंज ने पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला सोढ़ार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्तर की जानकारी ली, शिक्षण कार्य की गुणवत्ता का अवलोकन किया तथा विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षकों को विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने, नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धतियों को अपनाने तथा स्वच्छ एवं प्रेरक वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए।

इसी तरह पीएम श्री शासकीय प्राथमिक शाला किरना का जिला मिशन समन्वयक अशोक सोनी ने निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में संचालित गतिविधियों, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय व्यवस्था, मध्याह्न भोजन एवं छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने शिक्षकों से संवाद कर सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। गौरतलब है कि पीएमश्री योजना के तहत संचालित विद्यालयों की प्रतिमाह समीक्षा के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह अधिकारी नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण कर शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि इन विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कर विद्यार्थियों को उत्कृष्ट और समग्र शिक्षा प्रदान की जा सके।

महाविद्यालय वार्षिक उत्सव पर राजनीतिक विवाद, विरोध से पहले नेताओं की गिरफ्तारी

राजनांदगांव। राजनांदगांव। जिले के एक प्रमुख महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव को लेकर विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस मंच का इस्तेमाल एक विशेष राजनीतिक दल के प्रचार के लिए किया जा रहा है, जो विद्यार्थियों की प्रतिभा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य के खिलाफ है। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्यक्रम शैक्षणिक वातावरण से दूर हो चुका है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव हमेशा से छात्रों की उपलब्धियों और रचनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करने का अवसर रहा है, जिसमें दलगत राजनीति का कोई स्थान नहीं था। छात्रसंघ से जुड़े पूर्व पदाधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सभी छात्रों को समान अवसर और सम्मान देने की नीति अपनाई थी। नेताओं के मुताबिक, वे इस कार्यक्रम के कथित भाजपाकरण के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेताओं को उनके घरों से हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए विरोध जताया है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध करना उनका संविधानिक अधिकार है। हिरासत में लिए गए नेताओं में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के सचिव विशु अजमानी, पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री, एनएसयूआई नेता राजा यादव, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ऋषभ निर्मलकर, सागर ताम्रकार, संजय साहू और हनी सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। घटना के बाद कांग्रेस के पदाधिकारी बसंतपुर थाना पहुंचे और पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए नेताओं की रिहाई की मांग की। कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, प्रदेश सचिव मेहुल मारू, कांग्रेस नेता अमित चंद्रवंशी, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण साहू, संदीप जायसवाल और वीरेंद्र चंद्राकर ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्षता बरतने की अपील की है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रुकता है, तो वे इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे।

कृषक उन्नति योजना होली से पहले किसानों को बड़ी सौगात

जिले के 1.05 लाख से अधिक किसानों के खातों में 387 करोड़ रुपए से अधिक का होगा अंतरण

मुंगेली(समय दर्शन)कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को होली से पूर्व बड़ी राहत मिलने जा रही है। 28 फरवरी को बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम रहंगी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के किसानों से जुड़ेंगे और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की अंतर राशि का एकमुश्त अंतरण किसानों के बैंक खातों में करेंगे। जिले में इस योजना के तहत 01 लाख 05 हजार से अधिक किसानों के खातों में कुल 387 करोड़ 57 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। सभी विकासखंड मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री चयनित लाभार्थी किसानों से संवाद भी करेंगे। जिले में विकासखण्ड स्तरीय कार्यक्रम मुंगेली में कृषि उपज मंडी परिसर, लोरमी में मानस मंच एवं पथरिया में कार्या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी में आयोजित किया जाएगा। सीसीबी नोडल अधिकारी संतोष ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि लोरमी विकासखंड में 40 हजार 609 किसानों को 133.11 करोड़ रुपये, मुंगेली विकासखंड में 37 हजार 338 किसानों को 142.92 करोड़ रुपये तथा पथरिया विकासखंड में 27 हजार 765 किसानों को 111.53 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी और आगामी खेती कार्यों में सहूलियत होगी। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को विकासखंड स्तरीय आयोजनों में छाया, पेयजल, बैठक व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक किसान कार्यक्रम से जुड़ सकें। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। होली से पहले मिलने वाली यह सौगात किसानों के लिए उत्साह और विश्वास का संदेश लेकर आएगी।

पशु तस्कर पुलिस के शिकंजे में तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने 10 गोवंश पशुओं (भैंस) को तस्करों के चुंगल से छुड़ाया

सारँगढ बिलाईगढ़, सलिहा - (समय दर्शन) जिले में पशु तस्करी के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत सलिहा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है , पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशन पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति निमिषा पांडे अनु.अधि. पुलिस विजय ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले में घटित अपराधों तथा पशु तस्करी पर रोकथाम करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए इसके पालन में थाना प्रभारी सलिहा उप निरी पुरेन्द्र मल्होत्रा के नेतृत्व में पशु तस्करी करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार कर तीनों आरोपी को भेजा गया जेल होने संभावना अन्य आरोपी की संलिप्तता

विवरण- मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनाक 26/02/2026 को सूचना मिला कि दो नग वाहन 01. महेन्द्रा वीरो स्लेटी कलर का क्रमांक ष्ट्र 06-।ष्ट-8567, 02. महेन्द्रा वीरो सफेद रंग का क्रमांक ष्ट्र 04-त्तरू-0269 में भैंस एवं भैंसा मवेशी को क्रुरता पूर्वक भरकर बिलाईगढ तरफसे उडीसा ले जा रहे है कि सूचना पर थाना प्रभारी पुरेन्द्र मल्होत्रा के हमराह सउनि.देवनारायण साहू आरक्षक 68,388,283,254,271 के घेराबंदी कर वाहन 01. महेन्द्रा वीरो स्लेटी कलर क्रमांक ष्ट्र 06-।ष्ट-8567, 02. महेन्द्रा वीरो सफेद रंग क्रमांक ष्ट्र 04-त्तरू-0269 को पकड़ने से महेन्द्रा वीरो वाहन क्रमांक ष्ट्र 06-।ष्ट-8567 में 02 नग भैंस 03 नग भैंसा तथा दुसरे वाहन महेन्द्रा वीरो क्रमांक ष्ट्र 04-त्तरू-0269 में 02 नग भैंस 03 नग भैंसा कुल 10 नग ठुस ठुस कर क्रुरता पूर्वक भरा था जिस सम्बंध में चालक सूरज गुप्ता तथा दुसरे वाहन के चालक भीखम सिन्हा ने भैंस भैंसा मवेशी को उडीसा राज्य ले जाना बताये जिन्हें नोटिस देने पर वाहन में मवेशी परिवहन करने के सम्बंध में वैध दस्तावेज नहीं होना लिखित में दिये मौके पर देहाती नालसी लिया गया वाहन चालको सूरज गुप्ता, भीखम सिन्हा एवं केबिन में बैठे कबीर खान का मेमोरेंण्डम कथन लेकर वाहन महेन्द्रा वीरो क्रमांक ष्ट्र 06-।ष्ट-8567 एवं महेन्द्रा वीरो क्रमांक ष्ट्र 04-त्तरू-0269 में 05-05 नग भैंस, भैंसा मवेशी भरे किमती 1730000/रूपये तथा 04 नग मोबाईल फोन किमती 16300/रूपये जुमला किमती 1746300/रूपये को सूरज गुप्ता, भीखम सिन्हा, कबीर खान से जप्ती किया गया। आरोपीयों के द्वारा अपराध धारा 4,6,10 छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीयों के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना 01- सूरज गुप्ता पिता भगवान प्रसाद गुप्ता उम्र 42 साल साकिन कोमाखान सुवरमाल थाना कोमाखान जिला महासमुंद 02. भीखम सिन्हा पिता पुरूषोत्तम सिन्हा उम्र 25 साल साकिन बिहाझर थाना बागबहरा जिला महासमुंद 03. कबीर खान पिता रहीस खान उम्र 25 साल साकिन सागंज अर्जुन नगर चौराहा थाना सागंज जिला आगरा उत्तरप्रदेश हाल मुकाम ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नं 04 चांद होटल के पास थाना बंजारी जिला रायपुर छ.ग. से पुछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जो अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आज दिनांक 26/02/26 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सुचना उसके परिजन को देकर माननीय जेएमएफसी न्यायालय बिलाईगढ़ पेश कर रिमाण्ड पर भेजा गया है। जिसमें अन्य आरोपी की संलिप्तता होने की संभावना है।

संपूर्ण कार्यवाही में उप. निरी. पुरेन्द्र मल्होत्रा, सउनि देवनाराण साहू, आर. 68 राजेश नारंग, 388 रामकुमार पटेल, 283 आनंद पुरैना ,254 मिथलेश राय, 271 बलराम लहरे एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा

खबर-खास

संकल्प आधारित बजट भी ज्ञान और गति जैसे ढकोसला साबित होगा- रवि चन्द्रवंशी

किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रवि चन्द्रवंशी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पूर्ण रूप से निरंकुशता को दर्शाता है। किसान महिला युवा मज़दूर, ग्रामीण विकास को पीछे रखकर उद्योगपतियो को बढ़ावा देने वाला बजट है। जिस संकल्प को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का भाजपा सोच रही है वह सिर्फ़ और सिर्फ़ ढकोसला साबित होगा। इससे पहले जो ज्ञान और गति आधारित बजट बजट था वह पूर्ण रूप से असफ़ल साबित हुआ है। उसी तरह इस बजट का हश्र भी हो जाएगा।

सैमसंग इंडिया ने लॉन्च की अपनी सबसे एडवांस्ड AI फोन सीरीज़—गैलेक्सी S26; शानदार ऑफर्स के साथ प्री-ऑर्डर शुरू

गुरुग्राम। भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने घोषणा की है कि उसकी बहुप्रतीक्षित गैलेक्सी S26 सीरीज़ आज से भारत में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, गैलेक्सी S26+ और गैलेक्सी S26 अब तक का सबसे आसान और नैचुरल 'एजेंटिक एआई' मोबाइल अनुभव देते हैं। चाहे बात प्लानिंग की हो, जानकारी खोजने की या फिर कंटेंट को कैप्चर और एडिट करने की—गैलेक्सी S26 सीरीज़ हर काम को इतना आसान बना देती है कि यूजर्स को तकनीक की बारीकियों के बजाय सिर्फ बेहतरीन नतीजों पर ध्यान देना होता है। गैलेक्सी S26 सीरीज़ को सैमसंग की सबसे बेहतरीन खूबियों—दमदार परफॉर्मेंस, शानदार कैमरा सिस्टम और गैलेक्सी एआई—को मिलाकर तैयार किया गया है। यह तालमेल गैलेक्सी S26 यूजर्स को सुरक्षा या प्राइवेसी से समझौता किए बिना पूरे दिन बेधड़क अपने फोन पर निर्भर रहने का भरोसा देता है। डिस्प्ले तकनीक में दशकों के नवाचार को आगे बढ़ाते हुए, सैमसंग ने गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के साथ मोबाइल इंडस्ट्री का पहला इन-बिल्ट प्राइवेसी डिस्प्ले पेश किया है। यह पिक्सेल लेवल पर प्राइवेसी के प्रति सैमसंग की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में कस्टमाइज्ड चिपसेट और पहले से बेहतर थर्मल मैनेजमेंट भी दिया गया है, जो AI को और भी तेज और शक्तिशाली बनाता है - और यह सब अब तक के सबसे स्लिम (7.9 मिमी) अल्ट्रा डिज़ाइन में समाहित है। सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और सीईओ, जेबी पार्क ने कहा, गैलेक्सी S26 सीरीज़ को इस तरह बनाया गया है कि यह लोगों की जीवनशैली और काम करने के तरीके को गहराई से समझ सके। यह 'एजेंटिक एआई' के साथ सैमसंग की एक नई दिशा को दर्शाता है, जो रोजमर्रा के छोटे-मोटे कामों को खुद संभाल लेती है ताकि आप उन चीज़ों पर समय बिता सकें जो वास्तव में मायने रखती हैं—जैसे परिवार के साथ वक्त बिताना, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और लाइफ के हर पल का मजा लेना। इसके विकास में हमारे बेंगलुरु और नोएडा के रिसर्च सेंटर्स के इंजीनियर्स ने अहम भूमिका निभाई है। मुझे यह बताते हुए भी गर्व हो रहा है कि गैलेक्सी S26 सीरीज़ का निर्माण हमारी नोएडा स्थित फैक्ट्री में किया जाएगा।

सिन्टेक्स ने लॉन्च की 50 वर्ष की गारंटी वाली टंकी, शुरू किया अपना नया टीवी कैंपेन - पीढ़ियों तक भरोसा मजबूत करने की पहल

मुंबई। वेलस्पन वर्ल्ड की इकाई और भारत में गुणवत्तापूर्ण जल भंडारण समाधानों की अग्रणी एवं भरोसेमंद वॉटर स्टोरेज कंपनी, सिंटेक्स ने साइडवेज़ के साथ मिलकर नया टेलीविजन विज्ञापन अभियान शुरू किया है। इसके तहत 50 साल की गारंटी वाली पानी की टंकी 'सिंटेक्स इटर्नो' को प्रस्तुत किया गया है। इस विज्ञापन को आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान कनेक्टेड टीवी (CTV) पर दिखाया जाएगा। 20 सेकंड का यह विज्ञापन ब्रांड के वादे सबसे सेफ हमेशा पर आधारित है। अपने 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कंपनी ने 50 साल की गारंटी देकर लंबे समय तक टिकाऊपन और पीढ़ियों के भरोसे को रेखांकित किया है। यह 'इटर्नो' टैंक दशकों तक चलने के लिए बनाया गया है, जो सुरक्षा, स्वच्छता और पीढ़ियों के भरोसे का प्रतीक है। 'सिंटेक्स इटर्नो' को दशकों तक टिके रहने के लिए तैयार किया गया है। यह ब्रांड की दीर्घकालिक सोच तथा सुरक्षा, स्वच्छता, मजबूती और भरोसे के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जल प्रबंधन क्षेत्र में निरंतर नवाचार के लिए पहचानी जाने वाली कंपनी ने इस फिल्म के माध्यम से एक नया और ताज़ा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यह अभियान साइडवेज़ के सहयोग से तैयार किया गया है। 50 साल की गारंटी को केंद्र में रखते हुए, रचनात्मक टीम ने केवल उत्पाद की विशेषताओं के बजाय पीढ़ियों के दृष्टिकोण से कहानी प्रस्तुत की है। दुकान की पृष्ठभूमि में बने 20 सेकंड के इस विज्ञापन में एक हल्का लेकिन असरदार दृश्य दिखाया गया है।

महिला कांग्रेस ने किया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह का पुतलादहन, मांगा इस्तीफा

कवर्धा (समय दर्शन)। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती अल्का लांबा के निर्देशानुसार एवं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलों देवी नेताम के आदेशानुसार जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सीमा अनंत के नेतृत्व में ऐपस्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम होने को लेकर जिला मुख्यालय कबीरधाम में जोरदार धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया और केंद्रीय मंत्री से स्तीफा की मांग की गई।

महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सीमा ने बताया कि ऐपस्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम को लेकर जिला मुख्यालय कवर्धा में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया और पुतला दहन के साथ केंद्रीय मंत्री से स्तीफा की मांग की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कृत्य की भर्त्सना व निंदा करते हुए भाजपा मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की

इस्तीफे की मांग की गई है। यह घटना माफी योग्य नहीं है, बहुत ही शर्मनाक है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीमती ममता चंद्राकार राष्ट्रीय महासचिव महिला कांग्रेस, श्रीमती नारायणी टोडर अध्यक्ष शहर कांग्रेस, श्रीमती शारदा सोनवानी ब्लॉक अध्यक्ष, श्रीमती सीता ध्रुव पार्षद, रचना कोसले, वतन मेरावी, ज्योत्स्ना सत्यवशी, प्रीति ठाकुर, शुकल्या, नीला देवी पोर्टे, सीमा सरिया, सविता झरिया, श्यामवती, शालिनी, दीपिका, रानी चंद्रवंशी, गंगोत्री पनागर, चौती मसीह, पंचबाई, रोशनी खान, सीमा निर्मलकर, दुरपति, ऋतु पनागर, लता बाई, मंगला अनंत, किरण बाई, रामकुंवर, धनकी, मीना राजपूत, कलावती, क्रांति सेंडरे अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ता बहनों के साथ विशेष रूप से उपस्थित थी।

विश्व प्रोटीन दिवस पर आईबी ग्रुप का देशव्यापी अभियान, 2,500 से अधिक तहसीलों में हर घर हर दिन चिकन प्रोटीन की गूंज

रायपुर। विश्व प्रोटीन दिवस के अवसर पर देश की अग्रणी एग्री-फूड कंपनी आईबी ग्रुप ने हर घर हर दिन चिकन प्रोटीन शीर्षक से एक व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान संचालित किया। यह अभियान कश्मीर से कन्याकुमारी तक 20 राज्यों की 2,500 से अधिक तहसीलों में एक साथ चलाया गया, जिसका उद्देश्य भारत में महिलाओं और बच्चों में व्याप्त 73 प्रतिशत प्रोटीन कमी के प्रति जागरूकता फैलाना था। आंकड़ों के अनुसार देश में हर 10 में से 7 महिलाएं और बच्चे पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, जो एक गंभीर पोषण चुनौती बन चुकी है।

इस बड़े जनसंपर्क अभियान का मुख्य फोकस ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को उनके दैनिक आहार में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करने के महत्व के बारे में शिक्षित करना रहा। आईबी ग्रुप की टीमों ने गांवों और तहसीलों का दौरा कर सरपंचों, ग्राम प्रधानों और स्थानीय सम्मानित बुजुर्गों के साथ मिलकर जागरूकता बैठकों का आयोजन किया। इन सत्रों के दौरान परिवारों को बताया गया कि बच्चों के समुचित शारीरिक विकास और मस्तिष्क वृद्धि के लिए प्रतिदिन 25 से 50 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। महिलाओं को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और सामान्य स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखने के लिए 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, जबकि पुरुषों के लिए 55 से 70 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक है, ताकि थकान से बचाव हो और ऊर्जा का स्तर बना रहे। अभियान को व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए कई स्थानों पर चिकन से बनने वाले पौष्टिक और किफायती व्यंजनों का लाइव प्रदर्शन भी किया गया। ग्रामीण परिवारों को यह समझाया गया कि 100 ग्राम चिकन में लगभग 27 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन उपलब्ध होता है, जिसे नियमित भोजन में शामिल कर दैनिक आवश्यकता को सहज रूप से पूरा किया जा सकता है। आईबी ग्रुप के प्रबंध निदेशक बहादुर अली ने इस पहल पर कहा कि हर घर हर दिन चिकन प्रोटीन अभियान का उद्देश्य देश के हर गांव और हर परिवार तक प्रोटीन के महत्व का संदेश पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रोटीन की कमी विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है। आज पर्याप्त प्रोटीन लेना कोई विकल्प नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन, मजबूत प्रतिरोधक क्षमता और समग्र विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी का विजन है कि उच्च गुणवत्ता वाला,किफायती प्रोटीन हर घर तक पहुंचे और देश का कोई भी नागरिक प्रोटीन की कमी से प्रभावित न रहे। छत्तीसगढ़ में आईबी ग्रुप की टीम ने राज्य के 17 जिलों बलौदा बाज़ार, महासमुंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, धमतरी, कोंडागांव, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जांजगीर-चांपा,कोरबा, सक्ती, बिलासपुर, रायगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ की विभिन्न तहसीलों का व्यापक दौरा किया।

इंदौर में KWC Luxurio की शानदार एनिवर्सरी: रकुल प्रीत सिंह की मौजूदगी में सजा लग्ज़री और विरासत का जश्न

इंदौर में एक ग्लैमरस और यादगार शाम देखने को मिली, जब KWC Luxurio ने अपनी एनिवर्सरी के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह की मौजूदगी में एक खास पार्टी का आयोजन किया। शाम शानदार डेकोर, लाइव म्यूज़िक और खास मेहमानों, घड़ियों के शौकीनों और शहर के एलीट लोगों की मौजूदगी से और भी मज़ेदार हो गई। अपनी विज़िट के दौरान, रकुल प्रीत सिंह ने कुछ बढ़िया घड़ियाँ देखीं और कमल ग्रुप के डायरेक्टर से बातचीत की, जिससे उन्हें ब्रांड की विरासत और कारीगरी के बारे में जानकारी मिली — जिससे यह सेलिब्रेशन इंदौर में लग्ज़री रिटेल के लिए सचमुच एक खास पल बन गया। लगभग छह दशक पहले चेयरमैन श्री चांदमल तोतला द्वारा शुरू की गई, कमल वॉच कंपनी एक भरोसेमंद वॉच रिटेलर से बढ़कर प्रीमियम वॉच रिटेल में भारत के सबसे जाने-माने नामों में से एक बन गई है।

रेंज स्तरीय "ऑपरेशन निश्चय" के तहत आबकारी के 12 प्रकरण,आर्म्स एक्ट के 1 प्रकरण,4 स्थायी वारंट, 3 गिरफ्तारी वारंट तामिली के साथ 16 प्रकरण में प्रतिबकंधात्मक कार्यवाही किया गया

गरियाबंद (समय दर्शन)। "ऑपरेशन निश्चय"* के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज, रायपुर अमरेश मिश्रा के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में रेंज स्तर पर ऑपरेशन निश्चय चलाया जा रहा है।जिसके परिपालन में समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के द्वारा सुबह से अपने-अपने थाना क्षेत्रों में कुल 26 पुलिस टीम गठित कर 76 स्थानों में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान सभी थानों के द्वारा अबकारी एक्ट के 12 प्रकरणों में 12 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 96.820 लीटर अवैध शराब जप्त किये।साथ ही 1 प्रकरण आर्म्स एक्ट 1 आरोपी को गिरफ्तारी किया गया है। प्रकरण में जमानत पश्चात् काफी दिनों से फरार 4 स्थायी वारंटी तामिली एवं 3 गिरफ्तारी वारंट तामिली कर न्यायालय पेश किया गया है। आगीम होली त्योहार को ध्यान में रखते हुए थाना क्षेत्रों में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए 16 प्रकरणों में 17 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्क कार्यवाही किया गया है। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को हटाने की मांग, जांच टीम गठित

गरियाबंद (समय दर्शन)। जिला मुख्यालय से लगभग दस किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बारूका में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर लापरवाही और अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत बारूका के सरपंच-पंच, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्य तथा समस्त मितानिनों ने सामूहिक रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपते हुए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बारूका में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल हटाने की मांग की है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं एवं ग्रामीणों के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु संचालित योजनाओं का ग्राम बारूका में प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा न तो नियमित ग्राम भ्रमण किया जा रहा है और न ही आश्रित गांवों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

ग्रामीणों एवं समिति सदस्यों के अनुसार गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, बीपी-शुगर परीक्षण, सिकल सेल जांच, टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य

सेवाएं निर्धारित समय पर नहीं मिल रही हैं। आरोप यह भी है कि स्वास्थ्य जांच का अधिकांश कार्य मितानिनों द्वारा किए जाने के बावजूद उनकी रिपोर्ट विभागीय रजिस्टर में दर्ज कर शासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि अन्य कर्मचारियों द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। मितानिनों ने मानसिक प्रताड़ना की शिकायत भी की है। मामले की पड़ताल के दौरान मीडिया टीम ने बारूका एवं आसपास के गांवों की सात-आठ प्रसूता महिलाओं से चर्चा की। महिलाओं ने नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर बताया कि उनका प्रसव उनके घर पर हुआ था, जबकि विभागीय अभिलेखों में अस्पताल में प्रसव दर्ज किया गया है। महिलाओं का कहना है कि आज तक उन्हें किसी भी प्रकार की शासकीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुई, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ग्रामीणों के अनुसार बारूका स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम (महरू) पदस्थ नहीं है। एएनएम के स्थान पर वीरेंद्र नामक आरएचओ (क्राह्व) की पोस्टिंग की गई है, जो नियमित रूप से बारूका सहित अधीनस्थ गांवों का भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सीमित संसाधनों और स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए खंड चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है।

आगामी होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक लिया गया

इस होली हुड़दंगियों और यातायात नियमों का पालन नही करने वालों पर रहेगी पैनी नजर

गरियाबंद (समय दर्शन)। आगामी होली के इस पावन पर्व को शांति,आपसी भाईचारे और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने हेतु आज पुलिस अधीक्षक गरियाबंद वेदव्रत सिरमौर के दिशा-निर्देश एवं समस्त राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में एस.डीएम. तहसीलदार, कोतवाली प्रभारी, जनप्रतिनिधि ,ग्राम प्रमुखों एवं गणमान्य नागरियों की उपस्थित में शांति समिति की बैठक लिया गया।

बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों के द्वारा होली त्योहार को पारंपरिक गरिमा के साथ मनाने का संकल्प लिया। कोतवाली प्रभारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पर्व के दौरान हुड़दंग करने वाले,जबरन रंग डालने वाले या नशे की हालत में वाहन चलाने वाले,असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी और उनके विरुद्ध तत्काल दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में स्कूली बच्चों की परीक्षा को ध्यान में रखेते हुए डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक खबरों व अफवाहों से बचने और उनकी सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। बैठक में लिए गये निर्णय के संबंध में ग्राम कोटवारों को गांव में मुनियादी करने के निर्देष दिये गये है। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी नागरिकों से सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से होली उत्सव मनाने लोग अपनी सूझबूझ से मुख्य मार्ग में होली न जलाए साथ ही जहाँ बिजली का तार गया हो उसके नीचे न जलाए और हरेभरे पेड़ को नुकसान न पहुचाते हुए सरकारी संपत्ति का नुकसान न करे ।वही लोगो को हिदायत देते कहा कि अवैध चंदा वसूली ,तेज रफ्तार वाहन और अस्त्रशस्त्र लेकर न चलाने की समझाइश देते हुए त्योहार की शुभकामनाएं दिए।

जानकारी छुपाएंगे तो खायेंगे जेल की हवा

पोक्सो पर एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन

रायपुर। आज दिनांक 27 फ़रवरी 2026 को जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा मैट्स विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act)" विषय पर हितधारकों के लिए एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन मैट्स यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम, पंडरी, रायपुर में किया गया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु प्रावधानित कानूनों, विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन, बाल हितैषी न्याय प्रक्रिया तथा संबंधित विभागों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं स्वागत उद्बोधन श्री यशपाल जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया।

कार्यशाला में परिक्षेत्र पर्यवेक्षकों, पुलिस विभाग के अधिकारियों, जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग के अमलो तथा मैट्स विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं की सक्रिय सहभागिता रही। विषय विशेषज्ञ श्री विपिन ठाकुर, राज्य समन्वयक एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन छत्तीसगढ़, द्वारा पोक्सो एक्ट के तहत पीड़ित की पहचान करना उन्हें बाल कल्याण समिति के माध्यम से सहायता प्रदान

करना लैंगिक अपराधों से पीड़ित बच्चों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ प्रकरण को दर्ज करने की अनिवार्यता एवं अनिवार्य रिपोर्टिंग और झूठी रिपोर्टिंग के तहत सजा के प्रावधानों व पुलिस के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। प्रोफेसर दीनानाथ यादव मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा पॉक्सो अधिनियम के तहत समाज की भूमिका एवं उनके दायित्व के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष तिवारी के द्वारा पोक्सो एक्ट के तहत पीड़ित क्षतिपूर्ति तथा विधिक सहायता के संबंध में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने एक्ट की प्रमुख धाराओं, बाल अधिकारों, शिकायत एवं अन्वेषण प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन, पीड़ित बालकों के पुनर्वास एवं मनोसामाजिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

वक्ताओं ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने हेतु एक सशक्त एवं विशेष कानून है, जो त्वरित न्याय और बाल हितैषी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। साथ ही, उन्होंने सभी हितधारकों से अपील की कि वे अपने-अपने स्तर पर जागरूकता बढ़ाने, संदिग्ध मामलों की समय पर सूचना देने तथा पीड़ित बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न जिज्ञासाएँ एवं अनुभव साझा किए गए, जिनका विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया। यह कार्यशाला सुश्री शैल ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के दिशा निर्देश एवं श्री यशपाल, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन तथा श्रीमती माधुरी शर्मा जिला बाल संरक्षण अधिकारी के नेतृत्व में संजय निराला के समन्वय से आहुत किया गया। अंत में संजय निराला के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन किया गया।

यह कार्यशाला बाल संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता एवं समन्वित प्रयासों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई।

स्वामित्वधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक रोहित खड़तकर द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स ग्राम छाटा, पोस्ट देवादा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) 491111 से मुद्रित कर बी-4, प्रेस काम्प्लेक्स, इंदिरा मार्केट, दुर्ग छ.ग. 491001 से प्रकाशित। संपादक :- रोहित खड़तकर,
समाचार संपादक : दामोदर राव, फोन नं.-0788-4051213, मो. 9827104452, रायपुर कार्यालय:-0771-4218364, ईमेल - samay.darshan191@gmail.com पं. क्र. CHHHIN/2011/41517 डाक पंजीयन क्रमांक छ.ग./दुर्ग/61/2024-28

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25 वर्षों का उत्सव वर्षों का संकल्प

किसान हितैषी विष्णु सरकार

वृहद किसान सम्मेलन

दो साल में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के खाते में **₹1.50 लाख करोड़** से अधिक की राशि अंतरित

- **33,431 करोड़ रूपए** समर्थन मूल्य का भुगतान
- **3100 रूपए** प्रति क्विंटल की दर से राज्य के किसानों से प्रति एकड़ **21 क्विंटल** धान खरीदी
- वर्ष 2025-26 में **141.04 लाख मीट्रिक टन** की धान खरीदी
- **11,000 रुपए** प्रति एकड़ की दर से दलहन, तिलहन,मक्का,कपास, कोदो-कुटकी-रागी पर भी इनपुट सब्सिडी

जीएसटी 2.0 लागू होने से **कृषि उपकरण** हुए सस्ते

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दो साल में 26 लाख किसानों को **₹10,784 करोड़** वितरित

रबी सीज़न 2023-24 से 2025-26 के बीच
- खाद की खपत 41,84,850 मीट्रिक टन
- खाद सब्सिडी ₹7593.22 करोड़

कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि वितरण समारोह

सभी 146 विकासखण्डों में आयोजन

25.28 लाख किसानों के खातों में

₹10,324 करोड़

की आदान सहायता राशि होगी वितरित

बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान

- **₹600 करोड़** — दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना
- **₹5,500 करोड़** — विद्युत पम्पों हेतु बिजली सब्सिडी
- **₹820 करोड़** — प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- **₹250 करोड़** — इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान
- **₹170 करोड़** — उद्यानिकी विश्वविद्यालय
- **₹170 करोड़** — एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम
- **₹150 करोड़** — एकीकृत बागवानी विकास मिशन

28 फरवरी 2026

खेल मैदान रहंगी, बिल्हा, जिला-बिलासपुर

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in